रांची से प्रकाशित लोकप्रिय दैनिक

अलग पहचान

सत्य की उड़ान

गुरुवार
26 फरवरी -2026
वर्ष 10, अंक 173
पेज 8, मूल्य 2 रुपए
रांची

पेज-8

केन्द्र की सरकार का ओटीटी पर बड़ा चाबुक

● अश्लील कंटेंट वाले 5 ऐप्स किये ब्लॉक

पहले हटाए गए थे 100 से ज्यादा सीरीज

नई दिल्ली (एजेंसी)। ओटीटी पर दिखाए जाने वाले आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट पर भारत सरकार ने चाबुक चलाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अश्लील और वल्गर माने जाने वाले कंटेंट की स्ट्रीमिंग के लिए पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया। यह फैसला तब लिया गया, जब इन प्लेटफॉर्म्स को पहले कई बार चेतावनी जारी की गई, लेकिन

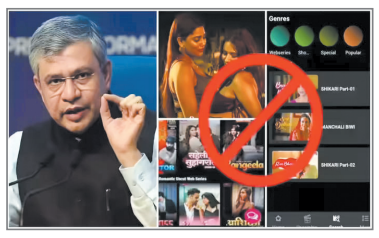

बावजूद इसके इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन नहीं किया। ब्लॉक किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म में मूड, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू ऐप शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 और अश्लीलता के खिलाफ कानूनों के तहत इन प्लेटफॉर्म तक पहुंच को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। इन नियमों का मकसद सार्वजनिक शालीनता की रक्षा करना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नैतिक मानकों को लागू करना है।

झारखंड विधानसभा में दामोदर नदी प्रदूषण पर हंगामा- वेदांता ईएसएल प्लांट पर लोगों का गंभीर आरोप

नदियों के प्रदूषण व अतिक्रमण का मामला, मंत्री बोले-हर माह रिपोर्ट होगी तैयार

दैनिक अलग पहचान, अन्नपूर्णा गुप्ता, मुख्य संपादक, नई दिल्ली/ झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन सदन में दामोदर नदी के बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। विधायक सरयू राय ने विशेष रूप से दामोदर नदी में औद्योगिक प्रदूषण, केमिकल डिस्चार्ज और अतिक्रमण के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों के सतत प्रयासों से कुछ समय पहले दामोदर नदी औद्योगिक प्रदूषण से लगभग मुक्त हो गई थी, लेकिन अब फिर से यह प्रभावित हो रही है। सरयू राय ने सदन में कई गंभीर आरोप लगाए, जिनमें दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह के ऐश पॉन्ड विस्तार में नदी क्षेत्र का अतिक्रमण, बोकारो ताप बिजली घर की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से दूषित बहिस्राव का कोनार नदी में गिरना और एनटीपीसी द्वारा टंडवा क्षेत्र में कोयला खनन से निकले दूषित पानी को सीधे दामोदर नदी में प्रवाहित करना शामिल है। इसके अलावा, बोकारो के वेदांता ईएसएल प्लांट पर स्थानीय लोगों ने गंभीर इल्जाम लगाया कि यह प्लांट केमिकल युक्त पानी नदी में बहा रहा है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। किसान संग्राम समिति की नेत्री सोनिया कुमारी मुर्मू ने आरोप लगाया कि प्लांट के खिलाफ आवाज उठाने वालों को या

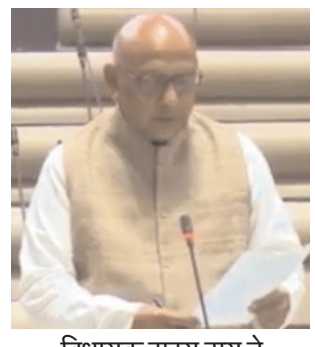

विधायक सरयू राय ने विधानसभा के पटल पर आवाज उठाते हुए (तस्वीर)

तो रिश्वत देकर मैनेज कर लिया जाता है या कानूनी जाल में फंसा दिया जाता है। उन्होंने सरकार से इस पर तत्काल गंभीर संज्ञान लेने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू (तस्वीर)

स्थानीय लोग भी वेदांता ईएसएल प्लांट के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट की गतिविधियां उनके स्वास्थ्य, कृषि और जल स्रोतों को प्रभावित कर रही हैं। वे प्रदर्शन और याचिकाओं के माध्यम से सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं, ताकि नदी को और प्रदूषित होने से बचाया जा सके। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिसने जांच पूरी कर आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग को हर महीने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनों (जैसे जल एवं वायु संरक्षण अधिनियम) का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि उल्लंघन के ठोस तथ्य सामने आते हैं, तो संबंधित एजेंसियों, कंपनियों या प्लांट्स के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। सरकार नदी की सफाई और प्रदूषण रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। दामोदर नदी झारखंड और पड़ोसी राज्यों के लाखों लोगों की जीवनरेखा है, लेकिन औद्योगिक गतिविधियों, खनन और प्लांट्स के डिस्चार्ज से यह लगातार प्रदूषित हो रही है। सरयू राय जैसे विधायकों द्वारा बार-बार यह मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इस पर अभी भी पर्याप्त और निर्णायक कार्रवाई नहीं हो रही है। वेदांता ईएसएल प्लांट सहित अन्य औद्योगिक इकाइयों पर लगे आरोपों पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि नदी को बचाया जा सके।

झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पोते की हुई मौत

● दवा खाने के बाद मुंह से निकला झाग, पुलिस जांच में खुले कई राज

मनाली (एजेंसी)। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की हिमाचल प्रदेश के मनाली में मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच में कई राज खुले हैं। वीर दोस्तों के साथ चार दिन पहले मनाली पहुंचा था। चर्चा थी कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने से उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। वीर

सोरेन की मंगलवार सुबह तबीयत ठीक नहीं थी। इस कारण वह दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया था और होम स्टे में ही रहा। दोपहर को दोस्त लौटे तो वीर ने सिरदर्द होने की बात बताई थी। दोस्तों ने उसे ऑनलाइन दवाई मंगवाई, जिसे खाने के बाद वह सो गया। लेकिन कुछ देर बाद कमरे से गिरने की आवाज आई तो उसके दोस्त अंदर गए। उन्होंने देखा वीर बिस्तर से नीचे गिर गया था। दोस्तों ने उसे सिविल अस्पताल मनाली पहुंचाया। अस्पताल ले जाते समय मुंह से झाग निकला। चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका।

40 साल बाद बाहर जाएगी नक्सली संगठन की कमान

● माओवाद के तेलंगाना युग का अंत, एक साल में ढेर हुए 10 टॉप कमांडर

रायपुर (एजेंसी)। माओवादी संगठन में पहली बार तेलंगाना कैडर से बाहर नेतृत्व जाने की संभावना है। थिप्पिरि तिरुपति उर्फ देवजी और मल्लाजी रेड्डी उर्फ संग्राम के समर्पण के बाद संगठन में नेतृत्व का संकट गहरा गया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये दोनों शीर्ष माओवादी तेलंगाना पुलिस की हिरासत में हैं। देवजी के समर्पण से

तेलंगाना कैडर का वह दबदबा खत्म हो रहा है, जो करीब 40 सालों से माओवादी हिंसा की दिशा तय कर रहा था। अब संगठन की कमान मिशिर बेसरा के हाथों में जाने की आशंका है। देवजी माओवादी संगठन के हिंसक दल का प्रमुख था और अनौपचारिक रूप से भाकपा (माओवादी) के महासचिव की भूमिका निभा रहा था। उसके समर्पण से तेलंगाना कैडर का वह वर्चस्व समाप्त हो गया है, जो पिछले चार दशकों से हिंसक गतिविधियों को निर्देशित कर रहा था। यह माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा झटका है। **तेलंगाना कैडर का इस साल बड़ा नुकसान**- वर्ष 2025 तेलंगाना कैडर के लिए विनाशकारी साबित हुआ है। मार्च 2026 तक माओवादी आंदोलन खत्म करना है।

एनसीईआरटी किताब में

'ज्यूडीशियल करप्शन' पर संग्राम

● चैप्टर पर सीजेआई का ऐक्शन, कहा-बदनाम करने की इजाजत नहीं

चीफ जस्टिस बोले-यह सोचा-समझा कदम लग रहा, केस खुद देखूंगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' का चैप्टर शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई है। सीजेआई ने कहा- किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस विपुल एम पंचोली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में यह मामला सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उठाया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा-मुझे इसकी पूरी जानकारी है।

किताब में लिखा, इंसाफ में देरी नाइंसाफी की तरह है

सोशल साइंस की इस किताब में लिखा गया है- इंसाफ में देरी नाइंसाफी की तरह है। यहां सुप्रीम कोर्ट में 81 हजार, हाईकोर्ट्स में 62 लाख 40 हजार, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के 4 करोड़ 70 लाख पेंडिंग केस की संख्या भी बताई गई है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक एम सिंघवी ने सीजेआई की बेंच के सामने कहा- बच्चों को ज्यूडिशियरी में करप्शन का सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे यह कहीं और, किसी और इंस्टीट्यूशन में है ही नहीं। यह चिंता का विषय है। हम यहां बार काउंसिल की चिंता लेकर आए हैं। दोनों वकीलों ने कहा, किताब में ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स वगैरह को छोड़ दिया है। दूसरे सेक्टर्स पर एक शब्द भी नहीं।

● **किताब में पूर्व सीजेआई बीआर गवई का भी जिक्र**- किताब में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस बीआर गवई का भी जिक्र है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामलों का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा था, हालांकि, इस ट्रस्ट को फिर से बनाने का रास्ता इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उठाए गए तेज, निर्णायक और ट्रांसपेरेंट एक्शन में है... ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक गुण हैं। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की सोशल साइंस का पार्ट 2 इसी हफ्ते जारी हुआ है। सीजेआई की टिप्पणी के बाद फिलहाल ये किताब एनसीईआरटी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक किताबों की ऑफलाइन बिक्री भी मंगलवार 24 फरवरी से बंद कर दी गई है। हालांकि अब तक एनसीईआरटी की तरफ इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है।

ट्रंप एक बार फिर बोले- भारत पाकिस्तान जंग हमने रुकवाई

● गाजा सीजफायर को बताया बड़ी जीत, वेनेजुएला बना नया दोस्त ● ईरान ने 32000 लोग मारे

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह संसद में भाषण दिया। साल की शुरुआत में संसद में प्रेसीडेंट के भाषण को 'स्टेट ऑफ द यूनियन' स्पीच कहा जाता है। ट्रम्प ने 1 घंटा 50 मिनट के भाषण में एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। ट्रम्प यह बात 100 से ज्यादा बार दोहरा चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हवाले से कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु जंग में 3.5 करोड़ लोगों के मारे जाने की आशंका थी। हालांकि, भारत इस दावे को हमेशा खारिज करता आया है। अपने भाषण में ट्रम्प ने इजराइल-हमास के बीच गाजा सीजफायर को अपनी उपलब्धि कहा। वहीं वेनेजुएला पर कब्जे के करीब डेढ़ महीने बाद वहां तेल उत्पादन में बढ़ोतरी का दावा करते हुए उसे अमेरिका का नया दोस्त करार दिया। ट्रम्प ने ईरान को लेकर दावा किया कि अमेरिका ने पिछले साल जुलाई में हमला कर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया था।

केरल में 5 लाख लोगों को वॉट्सएप पर मिला चुनावी मैसेज

● हाईकोर्ट की नाराजगी, बोला-ये निजता का गंभीर उल्लंघन

कोच्चि (एजेंसी)। केरल में सरकारी कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और विभिन्न लाभार्थियों सहित करीब 5 लाख लोगों को वॉट्सएप पर चुनावी संदेश भेजकर केरल सरकार घिर गई है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री कार्यालय को इनके मोबाइल नंबर कैसे मिले। कोर्ट ने डेटा सोर्स की पुष्टि तक ऐसे संदेश भेजने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि इस पहल में गोपनीयता की कमी है। साथ ही, संदेह जताया कि कहीं वेतन और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए बने एसपीएआरके पोर्टल का डेटा गलत तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय तक तो नहीं पहुंचाया गया। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक डेटा का राजनीतिक प्रचार के लिए उपयोग अनुच्छेद-21 के तहत निजता के अधिकार और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट ने पूछा है कि डेटा प्रोसेसिंग का कानूनी आधार क्या है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। याचिका में आरोप है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर विधानसभा चुनाव से पहले सीएम के फोटो वाले वॉट्सएप संदेश भेजे। इनमें 10 फीसदी डीए बढ़ोतरी जैसे काम गिनाए गए थे।

मुख्यमंत्री जन-वन योजना एवं अग्नि सुरक्षा को लेकर हुई बैठक

● डीएफओ प्रबल गर्ग ने ग्राम प्रधानों को उनकी भूमिका बताई

● राजमहल एसडीओ व रेंजर ने वन संरक्षण पर दिया जोर

दैनिक अलग पहचान, साहिबगंज ब्यूरो, ओम प्रकाश/साहिबगंज। (तालझारी) वन क्षेत्र कार्यालय, तालझारी में मुख्यमंत्री जन-वन योजना एवं वन अग्नि सुरक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य जंगलों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाना तथा वन संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल देना था। उपस्थित ग्राम प्रधानों एवं ग्रामीणों को बताया गया कि जंगल में लगने वाली आग से वन संपदा, वन्यजीव एवं पर्यावरण को भारी क्षति होती है। सभी से अपील की गई कि वे न स्वयं जंगल में आग लगाएँ और न ही

किसी को ऐसा करने दें।

इस अवसर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग ने सभी ग्रामवासियों एवं ग्राम प्रधानों से आग्रह किया कि यदि कहीं भी जंगल में आग लगने की सूचना मिले तो तत्काल वन विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते आग पर नियंत्रण पाया जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री जन-वन योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना जनसहभागिता के माध्यम से वन संरक्षण एवं संवर्धन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। राजमहल एसडीओ सदानंद महतो ने कहा कि

ग्राम प्रधान समाज की परंपरागत व्यवस्था है। जिनके माध्यम से सरकार की योजनाएं व सामाजिक सुधार की बातें जन-जन तक पहुंचती हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान अपने इलाके

के वन क्षेत्र की निगरानी करें। वनों के संरक्षण व संवर्धन भी हम सबका कर्तव्य है। एसडीओ ने कहा कि सभी ग्राम प्रधान जंगल व पेड़-पौधों को आग से जलने से बचाने के लिए गांव-गांव में बैठक कर ग्रामीणों को जागरूक करें। एसडीओ ने कहा कि वन विभाग की जमीन को लेकर कभी रैयत को कुछ परेशानी आती है। ऐसे में रैयत वन विभाग को अपनी ज़मीन का दस्तावेज प्रस्तुत कर उस डिस्प्यूट को समाप्त कर सकते हैं। लोग सरकार व वन विभाग की योजना से अपने जीवन मे खुशहाली लाएं। पर्यावरण प्रेमी सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ने अपने गीतों एवं कविताओं के माध्यम से लोगों को वन संरक्षण के प्रति जागरूक किया।

भारत बना रहा बेबी ब्रह्मोस, 20 गुना कम कीमत

● भविष्य की जंग की तैयारी, सुरक्षा का नया फॉर्मूला

नई दिल्ली (एजेंसी)। रूस-यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने साफ कर दिया है कि भविष्य की जंग अब महीनों और सालों खिंचेगी। इस हकीकत को देख भारत भी तैयारी में जुट गया है। सेना का फोकस अब केवल महंगी मिसाइलों पर नहीं, बल्कि इनके 'मिनी मॉडल्स' के बड़े भंडार पर है। हाल ही में पिनाका रॉकेट सिस्टम के 'हवाई संस्करण' के परीक्षण को इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल, ब्रह्मोस जैसी अचूक सटीकता और मारक क्षमता के कारण इसे 'बेबी ब्रह्मोस' भी कहा जा रहा है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने इस बदलाव को जरूरी बताते हुए कहा कि अगर हमारे पास किफायती लेकिन उच्च तकनीक वाले हथियार होंगे, तो हम लंबी जंग (हाई डेंसिटी वार) में किसी भी बड़े दुश्मन को पीछे धकेलने में सक्षम होंगे।

होली से पहले सीएम योगी का छात्रों को बड़ा तोहफा

स्कॉलरशिप की रकम बढ़ी, 38 लाख को होगा फायदा

लखनऊ (एजेंसी)। होली से ठीक पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टूडेंट्स को मिलने वाली स्कॉलरशिप की रकम बढ़ाने का फैसला लिया है। इसका सीधा लाभ राज्य के 38 लाख स्टूडेंट्स पर पड़ेगा। होली से पहले योगी सरकार ने 9वीं और 10वीं क्लास के छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ाने का फैसला किया है। 9वीं-10वीं के पिछड़े वर्ग के छात्रों को पहले 2250 रुपये छात्रवृत्ति मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 3000 रुपये कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने छात्रवृत्ति वृद्धि का श्रेय मुख्यमंत्री को दिया। यूपी सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों को एक और बड़ी राहत दी है। छात्रवत्ति एवं शुल्क भरपाई के लिए ओबीसी वर्ग के छात्रों के माता-पिता व अभिभावकों की आय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे छात्रवृत्ति का लाभ उठाने वाले छात्रों को दायरा बढ़ेगा। राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के अभिभावकों की आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना कर दी गई है।

अब 25 सितंबर से दी जाती है छात्रवृत्ति

उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत साल 2023-24 से एक भी विद्यार्थी नहीं छूटा है। पहले 31 मार्च को छात्रवृत्ति दी जाती थी, अब योगी सरकार में 25 सितंबर से छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। उन्होंने बताया कि छात्रों के साथ-साथ दिव्यांगजन पेंशन राशि 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी।

बिहार में फर्जी शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई

टीचर बनने के लिए निकाला था जुगाड़, अब वसूला जाएगा पूरा वेतन

पटना (एजेंसी)। बिहार में लाखों युवा चौथे चरण की टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच बीपीएससी टीआरई-1 में फर्जी तरीके टीचर बनने का मामला सामने आया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया की ओर से जारी एक अधिसूचना में फर्जी शिक्षक पर बड़ी कार्रवाई की सूचना दी गई। साथ ही बताया कि गलत तरीके से टीचर बनने वाले को न सिर्फ सरकारी नौकरी से निकाले जाएगा, बल्कि पूरा वेतन भी वसूला जाएगा। दरअसल, बीपीएससी टीआरई-1 में विजय कुमार के नाम शख्स को कंप्यूटर साइंस टीचर की नौकरी मिली थी। वह पूर्णिया के स्कूल में 11वीं-12वीं क्लास को कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे थे लेकिन अब सामने आया है कि विजय ने टीचर बनने के लिए जुगाड़ निकाला था।

● **नौकरी से निकाला, अब वसूला जाएगा पूरा वेतन**- 9 अक्टूबर 2025 को विजय कुमार से पूछताछ की गई। विभागीय जांच के बाद सभी आरोप सही पाए गए। जांच में साबित हुआ कि विजय कुमार ने बिना पात्रता के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हासिल की थी। जिला शिक्षा अधिकारी, पूर्णिया ने 2 शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही अब वेतन वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक के तहत बिहार में फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त करने के साथ पूरा वेतन वसूलने का नियम है।

संक्षिप्त समाचार

बच्चा चोरी के अफवाह में तीन महिलाओं की पिटाई, धनबाद पुलिस ने महिलाओं को बचाया

धनबाद, एजेंसी। धनबाद में बुधवार को बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ का गुस्सा सामने आया। ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के निछानी पुल के पास तीन महिलाओं को बच्चा चोर समझकर पीटा गया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी पर भी चप्पल और जूते फेंके गए। यह घटना ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र के निछानी पुल के पास हुई। बच्चा चोरी की अफवाह फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने तीन महिलाओं को पकड़ लिया और उनके साथ लात-घूंसों व जूतों से मारपीट की। पीटने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वाहन पर भी चप्पल और जूते फेंके। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद तीनों महिलाओं को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला और थाने ले गई। पुलिस ने बताया कि बच्चा चोरी की सूचना की जांच की जा रही है और फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून को हाथ में न लेने की अपील की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इलाके में शांति बनाए रखने का प्रयास कर रही है।

6 साल के मासूम ने जाते-जाते 2 लोगों की जिंदगी में भर दी रोशनी

रांची, एजेंसी। रिम्स क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक परिवार ने अपने छह वर्षीय बेटे के निधन के बाद उसका नेत्रदान कर दो लोगों को नई रोशनी दी। रिम्स आई बैंक की टीम ने तत्परता दिखाते हुए प्रक्रिया पूरी की और दोनों कार्निया का सफल प्रत्यारोपण किया। प्रबंधन ने जानकारी दी कि पिछले सप्ताह होचर कांके निवासी सुजीत मुंडा के छह वर्षीय बेटे का इलाज रिम्स में चल रहा था। वह न्यूरोसर्जरी विभाग में भर्ती था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस कठिन घड़ी में भी परिजनों ने साहस का परिचय देते हुए नेत्रदान का निर्णय लिया। रिम्स आई बैंक की टीम ने परिवार से संपर्क कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की और निकाले गए कार्निया को आई बैंक में सुरक्षित रखा। रिम्स नेत्र विभाग के एचओडी डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि कि दोनों कार्निया का सफल उपयोग कर दो जरूरतमंद दृष्टिहीन मरीजों में कार्निया प्रत्यारोपण किया गया। अब वे दोनों मरीज देख पा रहे हैं। यह अभी तक का सबसे कम उम्र का नेत्र दान रहा है। चिकित्सकों के अनुसार कार्निया को मृत्यु के छह घंटे के भीतर सुरक्षित निकालना आवश्यक होता है, ताकि उनका सफल प्रत्यारोपण किया जा सके। बच्चे के स्वजनों ने भावुक होते हुए कहा कि उनका बेटा भले इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी आंखें अब किसी और की दुनिया रोशन कर रही हैं। यह कदम समाज के लिए प्रेरणादायक संदेश है कि मृत्यु के बाद भी जीवन बांटा जा सकता है। चिकित्सकों ने इसे समाज के लिए प्रेरक पहल बताया और अधिक से अधिक लोगों से नेत्रदान का संकल्प लेने की अपील की है।

झारखंड में खुलेंगे 100 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस

रांची, एजेंसी। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 नए सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस (उत्कृष्ट विद्यालय) खोलेगी। इसके लिए न केवल स्कूलों का चयन कर लिया है, जिन्हें इस विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा, बल्कि इसपर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब इसपर कैबिनेट की स्वीकृति ली जानी है। वहीं, राज्य सरकार राज्य के सरकारी व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पढ़नेवाली लगभग 12 लाख छात्राओं को सेनेटरी पैड उपलब्ध कराएगी। इसपर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शुरू होनेवाली इस योजना की स्वीकृति विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति से ली जाएगी। मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत होनेवाले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में हालांकि इन दोनों योजनाएं सम्मिलित नहीं हैं। बताया जाता है कि 100 सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पास पहले से ही राशि उपलब्ध है। वहीं, 12 लाख छात्राओं के सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने के विभाग के निर्णय से पहले ही बजट तैयार हो गया। अब इसके लिए पहले अनुपूरक बजट में राशि का प्रविधान किया जा सकता है। इधर, विभागीय सूत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के बजट में कोई नई योजना नहीं ली गई है। पुरानी योजनाओं के लिए राशि का प्रविधान किया गया है। वहीं, बजट आकार भी पिछले वित्तीय वर्ष के ही लगभग समान है। स्वास्थ्य विभाग के बजट में हृदय रोग एवं कैंसर की जांच तथा इलाज के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके तहत सभी मेडिकल कालेजों में हृदय रोग के इलाज के लिए कैथ लैब की स्थापना की जाएगी। स्तन कैंसर की जांच के लिए सभी सदर अस्पताल में मेमोग्राफी जांच की सुविधा बहाल की जाएगी। वहीं, कैंसर की जांच के लिए मेडिकल कालेजों तथा सदर अस्पताल में पेट स्कैनर सेंटर खोलने की योजना ली गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए बड़ी राशि का प्रविधान बजट में किया जा सकता है। रांची में एक अन्य मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए भी राशि का प्रविधान होगा।

प्रदेश में सड़कों का मेगा प्लानः 785 किमी सड़क उन्नयन,

35 नए फ्लाईओवर और 6,601 करोड़ का ब्लूप्रिंट

रांची, एजेंसी। राज्य में आधारभूत संरचना के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से पथ निर्माण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए व्यापक योजना तैयार की है। सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेशन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम होती हैं।

यही कारण है कि राज्य सरकार ने सड़क नेटवर्क के विस्तार और गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया है। राज्य गठन के समय जहां कुल सड़कों की लंबाई मात्र 5,400 किलोमीटर थी, वहीं अब यह बढ़कर 15,066 किलोमीटर हो गई है।

इसी प्रकार पथ घनत्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2025-26 के प्रारंभ में यह 186 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में बढ़कर 189.03 किलोमीटर हो गया है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य तेजी से आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।

राज्य सरकार ने यातायात व्यवस्था को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रमुख सड़कों को फोर लेन में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। राजधानी रांची सहित राज्य के सभी प्रमुख शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर फ्लाईओवर निर्माण की योजना बनाई गई है।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल यात्रा समय को

कम करना है, बल्कि ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी लाना भी है। आने वाले समय में इन प्रयासों से शहरी यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

पथ निर्माण विभाग ने सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आइआरक्यूपी (इंप्रूवमेंट आफ राइडिंग क्वालिटी प्रोग्राम) लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत क्षतिग्रस्त और जर्जर सड़कों की मरम्मत कर उन्हें बेहतर बनाया जाएगा।

यह योजना विशेष रूप से उन सड़कों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन पर भारी यातायात का दबाव रहता है। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि यात्रियों को भी सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा।

राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई पुराने और क्षतिग्रस्त पुल यातायात में बाधा बन रहे हैं। इन्हें 'बॉटल नेक' के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे पुलों को हटाकर उनकी जगह नए, आधुनिक और उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

यह कदम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए लाभकारी होगा, जिससे आवागमन में निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

सड़क और रेल मार्ग के बीच होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा लेवल क्रॉसिंग समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

इस दिशा में पथ निर्माण विभाग और रेल मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित कर विभिन्न स्थानों पर रोड ओवरब्रिज निर्माण की योजना बनाई गई है। इस पहल से जहां दुर्घटनाओं में कमी आएगी, वहीं यातायात भी निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में पथ निर्माण विभाग ने पथ घनत्व को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत 785 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन का प्रस्ताव है। साथ ही, पहले से निर्मित 1,200 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण और उनकी गुणवत्ता सुधार पर भी काम किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त 35 स्वतंत्र उच्चस्तरीय फ्लाईओवर और रोड ओवरब्रिज के निर्माण की भी योजना है, जो राज्य की यातायात व्यवस्था को नई दिशा देंगे।

इन सभी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में पथ निर्माण विभाग के लिए 6,601 करोड़ 28 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। यह बजट सड़कों के विस्तार और उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

गिरिडीह में निकाय चुनाव के बाद हिंसा मामला: पांच गिरफ्तार, हथियार बरामद

गिरिडीह, एजेंसी। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव के बाद वार्ड संख्या 18 में हुई हिंसक घटना के संबंध में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में दो लोग गोली लगने से घायल हुए थे। यह घटना 23 फरवरी की शाम करीब 5:30 बजे उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, आजाद नगर अनुजाति टोला स्थित मतदान केंद्र के पास हुई थी। किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो जल्द ही मारपीट और पत्थरबाजी में बदल गया।

तनावपूर्ण स्थिति के दौरान भीड़ में से किसी ने गोली चला दी, जिससे मोहम्मद शमीम और मोहम्मद शेरू घायल हो गए। दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर-बितर किया। मामले में प्राप्त आवेदन के आधार पर पचंबा थाना में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। रबीना खातून के बयान पर घायल मोहम्मद शमीम और मोहम्मद शेरू के संबंध में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष अनुसंधान दल का गठन किया।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जितवाहन उरांव के नेतृत्व में चार टीमों ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान शिवम कुमार श्रीवास्तव उर्फ शिवम आजाद, अमित विश्वकर्मा, आकाश हांडी, मंजीत पासवान और किशोर पासवान को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर एक 7.65 एमएम का देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बरामद हथियार और अन्य सामान जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पूछताछ में घटना से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन का कुल्लू में संदिग्ध निधन

सरायकेला, एजेंसी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के परिवार से एक अत्यंत ही दुखद खबर सामने आ रही है. उनके 19 वर्षीय पोते वीर सोरेन की हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. वीर सोरेन बाहर रहकर अपनी शिक्षा पूरी कर रहे थे. प्राप्त जानकारी के अनुसार, वीर सोरेन मंगलवार को अपने मित्रों के साथ कुल्लू भ्रमण पर गए थे. बताया जा रहा है कि बर्फ में स्केटिंग का आनंद लेने के बाद जब वे वापस होटल लौटे, तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. स्थिति इतनी तेजी से खराब हुई कि उन्हें अस्पताल ले जाने तक का समय नहीं मिल सका और होटल में ही उन्होंने अंतिम सांस ली. हालांकि, मौत के सटीक कारणों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी शेष है.

बताया गया कि वे मनाली दोस्तों के साथ घुमने गए थे। देर रात होटल में ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी। साथियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि उन्हें अस्पताल तक ले जाने का अवसर नहीं

मिल सका। होटल में ही उनका निधन हो गया। घटना के बाद साथ मौजूद मित्रों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

प्रारंभिक तौर पर मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे घटना को संदिग्ध माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गहरे सदमे में हैं. वे अपने पुत्रों के साथ मंगलवार देर रात ही रांची से हवाई मार्ग द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां से वे कुल्लू पहुंचेंगे. चंपाई सोरेन के पैतृक गांव में चल रहे सभी पारंपरिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है. चंपई सोरेन के गांव झिलिंगगोड़ा सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है. परिवार की ओर से जारी शोक संदेश में कहा गया है: 'अत्यंत दुःख के साथ सूचित करते हैं कि हमारे प्रिय वीर सोरेन का 24 फरवरी 2026 को असामयिक निधन हो गया है. हिमाचल प्रदेश के मनाली में अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. वीर के जाने से हमारा परिवार बिखर गया है'.

10 साल पहले लापता हुए पलामू के युवक ने पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर से किया बरामद

पलामू, एजेंसी। जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के काला पहाड़ इलाके का रहने वाला मंगल परहिया 2016 में लापता हो गया था. लापता होने के समय उसकी उम्र करीब 10 साल थी. पलामू पुलिस ने लापता युवक को पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर से बरामद किया. 2016 में मंगल परहिया अपने माता-पिता के साथ कोलकाता गया था. वहीं वह लापता हो गया था. उसके परिवार ने कई महीनों तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई. उन्होंने अपने स्तर से ही उसकी खोजबीन की. दिसंबर 2025 में मंगल परहिया के माता-पिता पलामू एसपी रीष्मा रमेशन से मिले और उसके लापता होने की सूचना दी.

पलामू एसपी के निर्देश पर छतरपुर एसडीपीओ अवध कुमार यादव और छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई गई. इस टीम ने मानवीय सूचना और टेक्निकल जांच के आधार पर मंगल परहिया की तलाश शुरू की. इसी क्रम में पलामू पुलिस को पता चला कि मंगल पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बांग्लादेश बॉर्डर के पास है.

इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए छतरपुर थाना पुलिस पश्चिम बंगाल गई और मंगल परहिया को बरामद कर लिया. मंगल को उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है. मंगल परहिया 21 साल का है और 24 परगना में मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था.

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि मंगल के माता-पिता उनसे मिलने आए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. मंगल को 24 परगना जिले से बरामद किया गया.

कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर, अब जेपीएससी या जेएसएससी करेगी नेतरहाट स्कूल में नियुक्तियां

रांची, एजेंसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाते हुए विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों में नामांकित छात्र-छात्राओं को राहत दी है. वे अब परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और परीक्षा दे सकेंगे.

नगर निकाय चुनाव आचार संहिता के कारण इस संबंध में कोई आधिकारिक ब्रीफिंग नहीं की गई. मगर, कैबिनेट विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य के कई निजी नर्सिंग कॉलेजों में झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा पर्षद की काउंसिलिंग के बिना ही छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ था. निजी नर्सिंग कॉलजों की ओर से सीधे नामांकन ले लिया गया था. इससे उन्हें परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया गया.

झारखंड सरकार ने ऐसे नर्सिंग कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को राहत देते हुए तय नियमों को एक बार शिथिल करने का फैसला लिया है. इस फैसले से निजी नर्सिंग कॉलजों द्वारा नामांकित कर लिए गए छात्र-छात्राओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल सकेगी. निजी नर्सिंग कॉलेजों ने संस्था के तकनीकी मान्यता नहीं मिलने के बावजूद नर्सिंग कोर्स में नामांकन ले लिया था. इस कारण झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलोजी की ओर से उनकी परीक्षा नहीं ली जा रही थी. अब राज्य सरकार की ओर से छूट

दिए जाने के बाद ऐसे छात्र-छात्राएं परीक्षा में बैठ सकेंगे और नर्सिंग की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे.

कैबिनेट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति संबंधी नियमावली में बदलाव किया है. अब विद्यालय के प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति जेपीएससी या जेएसएससी के माध्यम से होगी. राज्य सरकार ने जनवरी में नेतरहाट आवासीय विद्यालय संचालन नियमावली को भी स्वीकृति दी थी. उसमें चार बॉडी का गठन किया गया था. एपेक्स बॉडी मुख्यमंत्री, जेनरल बॉडी विभागीय मंत्री, तीसरा कार्यकारिणी समिति सभापति की अध्यक्षता में गठित करने और चौथा विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है. अब सभापति एक्स नेतरहाटीयन होंगे, लेकिन उनके लिए योग्यता निर्धारित कर दी गयी है.

कैबिनेट की बैठक में चाईबासा क्षेत्र में अबुआ आवास निर्माण संबंधी प्रस्ताव भी आया. इसमें एस्बेस्टस और सीट से निर्माण की बात कही गयी थी. जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को स्थगित करते हुए ग्रामीण विकास विभाग को नये सिरे से प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है. उसमें उस क्षेत्र के लोगों के रहन सहन को ध्यान में रखते हुए अबुआ आवास निर्माण की प्रक्रिया निर्धारित करने की बात कही गयी है. खपड़ा, टाइल्स या उस क्षेत्र में पाए जाने वाले भवन निर्माण संबंधी मैटेरियल का उपयोग अबुआ आवास के निर्माण किया जाए.

ओडिशा से यूपी जा रहा था 8 लाख का गांजा, रांची में आरपीएफ ने दो को दबोचा

रांची, एजेंसी। रेलवे स्टेशन परिसर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आरपीएफ पोस्ट रांची एवं फ्लाइंग टीम रांची ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में 16 किलोग्राम गांजा बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रांची रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया गया।

ट्रेन संख्या 18309 एक्सप्रेस के रांची पहुंचने पर कोच संख्या एस-7 की तलाशी ली गई। सीट संख्या चार पर बैठे एक व्यक्ति के पास नीले रंग का पिट्ठू बैग संदिग्ध अवस्था में मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहन सिंह (41 वर्ष), निवासी सुंदरगढ़, ओडिशा बताया। बैग की जांच में भूरे प्लास्टिक में लिपटा गांजा बरामद हुआ।

मोहन सिंह के बयान पर उसी कोच की सीट संख्या 64 पर बैठे राहुल पांडेय (32 वर्ष), निवासी गाजीपुर, उत्तर प्रदेश की तलाशी ली गई। उसके लाल एवं ग्रे रंग के बैग से भी गांजा बरामद किया गया।

सहायक सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर विधिवत तलाशी में कुल आठ पैकेट गांजा (पांच मोहन सिंह के पास से एवं तीन राहुल पांडेय के पास से) जब्त किए गए। बरामद गांजा का कुल वजन 16 किलोग्राम एवं अनुमानित कीमत लगभग आठ लाख रुपये आंकी गई। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे ओडिशा से गांजा खरीदकर उत्तर प्रदेश में अवैध बिक्री के लिए ले जा रहे थे।

एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 20(बी)(टू)(बी)/29 के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को 24 फरवरी 2026 को जब्त माल सहित जीआरपी रांची को सौंप दिया गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक शिशुपाल कुमार, उपनिरीक्षक सूरज पांडेय, एएसआई अनिल कुमार, स्टाफ रामकृष्ण, दिनेश प्रसाद, हेमंत सहित आरपीएफ पोस्ट एवं फ्लाइंग टीम रांची के सदस्यों की भूमिका रही।

दशम और जोन्हा में ग्लास ब्रिजः पतरातू में स्काईवॉक, हुंडरू में रोपवे

रांची, एजेंसी। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को प्रस्तुत आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए भी अपनी झोली खोली है।

आगामी वित्तीय वर्ष में पर्यटन विभाग के लिए 361.67 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है। इस राशि को पर्यटकों की सुख-सुविधा आदि पर खर्च किया जाएगा।आने वाले वित्तीय वर्ष में रांची के दशम जलप्रपात पर ग्लास ब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव है। वहीं, जोन्हा जलप्रपात पर ग्लास ब्रिज व रोपवे का निर्माण तथा हुंडरू जलप्रपात पर रोपवे का निर्माण व विकास कार्य कराया जाना है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा व पतरातू के विकास को भी सरकार ने अपने बजट में शामिल किया है। आगामी वित्तीय वर्ष में रामगढ़ जिले के रजरप्पा में पर्यटकीय विकास की योजना है।

वहीं, जिले के पतरातू में स्काईवॉक का निर्माण होगा। वहां पतरातू जलाशय में सोलर बोट तथा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाना है। वित्त

मंत्री ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में लातेहार जिले के नेतरहाट में कोयल व्यू प्वाइंट पर ग्लास वॉच टावर व मैगनोलिया प्वाइंट पर स्काई वॉक का निर्माण कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने देवघर के पुनासी डैम के पर्यटकीय विकास की घोषणा की। उन्होंने पलामू जिलांतर्गत मलय डैम का पर्यटकीय विकास व चतरा जिलांतर्गत कोलेश्वरी पहाड़ में रोपवे के निर्माण की घोषणा की है।

यह भी कहा कि खूंटी जिले के पेरवाघाघ जलप्रपात तथा पांडू-पुडिंग पिकनिक स्थल के इको पर्यटन सर्किट का विकास कार्य कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि खनन पर्यटन विकसित करने के लिए इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (आइटीडीसीएल) व सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सीसीएल) के साथ एमओयू होगा।

पर्यटन कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के माध्यम से वर्तमान में आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र एवं 102 डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोलने का लक्ष्य है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के मौजा कर्णपुरा में आउटडोर स्टेडियम की स्वीकृति दी गई है। दुमका जिले के कमार दुधानी में आउटडोर स्टेडियम में आठ लेन का आधुनिक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। सिल्ली प्रखंड में संचालित आवासीय तीरंदाजी क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में 25 शैय्या वाले खेल छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधीन कई जिलों में निरीक्षण भवन, रेस्ट हाउस, परिसदन आदि निर्मित हैं। इसके परिसर में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर अन्य सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव है। राज्य में झारखंड संगीत नाटक अकादमी, झारखंड ललित कला अकादमी व क्षेत्रीय भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी का गठन नियमावली अधिसूचित कर दिया गया है। राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र सरायकेला के सुचारू रूप से संचालन के निमित्त कार्यकारी एवं स्थाई समितियों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है।

संक्षिप्त समाचार

तरा प्लेन क्रैश के मृतकों के परिवार से मंत्री इरफान अंसारी ने की मुलाकात

चतरा, एजेंसी। झारखंड के चतरा जिले में हुए दुखद एयर एम्बुलेंस क्रैश के बाद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी चतरा पहुंचे. उन्होंने सदर अस्पताल में मृतकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी. उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए बहुत दुखद घटना थी और अब तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश था. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन की तुरंत कार्रवाई से सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और उसमें सवार सभी लोगों के शव बरामद कर लिए गए. उन्होंने कहा कि सभी शवों का पोस्टमॉर्टम होने के बाद उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था की दयनीय हालत के कारण मरीज को दिल्ली ले जाया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि प्लेन क्रैश के कारणों की जांच की जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि प्लेन क्रैश का कारण जांच का विषय है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को भरोसा दिलाया कि झारखंड सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ है. उन्होंने प्लेन क्रैश को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि अलग-अलग राज्यों में बार-बार प्लेन क्रैश हो रहे हैं. केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है. केंद्र सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है. वहीं चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि यह सात परिवारों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है. उन्होंने भगवान से सभी परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की. उन्होंने प्लेन क्रैश की हाई-लेवल जांच और मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की. विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है और पूरे क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने कहा कि सरकार को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और आर्थिक सहयोग देनी चाहिए. उन्होंने यह हादसे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

मौसम का बदला मिजाज: तेज हवा के साथ बारिश ने गिराया तापमान

रांची, एजेंसी। झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। एक ओर जहां चुनावी मौसम में पूरा शहर डूबा था तो वहीं, सोमवार की रात आठ बजे अचानक तेज हवाओं ने पूरे शहर को धूल-धुसरित कर दिया। तेज हवा के साथ बूंदाबांदी ने तापमान गिरा दिया है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो पूरे राज्य का मौसम शुष्क बना रहा जबकि दिन में गर्मी का अहसास हुआ। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12 डिग्री गुमला का रिकार्ड किया गया। वहीं, राजधानी रांची का अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। हालांकि, सोमवार को तेज हवा और कई जगहों पर बूंदाबांदी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। लगातार बढ़ रहे तापमान के कम होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि पूरे राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले तीन दिनों तक यानी 25, 26 ओर 27 फरवरी को तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। वहीं, 24 फरवरी को राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे। राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी, इन हिस्सों के करीब 13 जिलों में मेघगर्जन के साथ वर्षा होने की पूरी संभावना है।

टेकऑफ के 23 मिनट बाद कट गया कनेक्शन, सामने आई चतरा एयर एंबुलेंस हादसे की पूरी कहानी

रांची, एजेंसी। झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एंबुलेंस सोमवार शाम को झारखंड के चतरा जिले में क्रैश हो गई, जिसमें सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। एयरक्राफ्ट ने टेकऑफ के तुरंत बाद खराब मौसम की वजह से डायवर्जन की रिक्वेस्ट की थी,लेकिन फ़्लाइट शुरू होने के आधे घंटे से भी कम समय में यह रडार से गायब हो गया। आग से गंभीर रूप से झुलसे लातेहार के सरोजनगर चंदवा निवासी मरीज 41 वर्षीय संजय कुमार रांची के देवकमल अस्पताल में 16 फरवरी से भर्ती थे। पलामू के सतबरवा में होटल चलाने वाले संजय पिछले दिनों अपने होटल में झुलसने के बाद यहां लाए गए थे। सोमवार शाम उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट किया गया। रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड की बीचक्राफ्ट सी 90 एयर एंबुलेंस ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शाम 7.11 बजे उड़ान भरी। इसे 8.30 बजे दिल्ली पहुंचना था। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक बिनोद कुमार ने बताया कि शाम 7.34 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान का संपर्क टूट गया, तत्काल हाई अलर्ट जारी कर दिया गया।वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक, विमान उनके एयरस्पेस में प्रवेश के बाद संपर्क में नहीं आया था। इसके बाद रात करीब 8 :05 बजे रेस्क्यू को-आर्डिनेशन सेंटर को सक्रिय किया गया और तलाश अभियान शुरू किया गया। कुछ देर बाद चतरा और सिमरिया सीमा क्षेत्र में क्रैश होने की सूचना मिली।

बजट: किसानों को ऋण मुक्त कर आय बढ़ाने पर जोर

महिला किसानों के लिए नई योजना

रांची, एजेंसी। बजट पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह भविष्य की उम्मीद को नई उड़ान देने जैसा है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने एक लाख 58 हजार 560 करोड़ का बजट पेश किया है। जिसमें कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का बजट चार हजार 884 करोड़ 20 लाख रुपये का शामिल है। यह बजट गरीबों के दुख दर्द को कम करने और राज्य वासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट है।

इस बजट में सभी जाति-धर्म-वर्ग को साथ लेकर चलने और उनके विकास का संकल्प समाहित है। इस बजट में जमीनी हकीकत का समावेश, राज्य के विकास की योजना, आर्थिक स्रोत के मजबूती कारण का फार्मूला, गांव के विकास और किसान के घर खुशहाली की दीर्घकालिक योजना है। राज्य के समावेशी विकास, आदिवासी अस्मिता की रक्षा और आत्म निर्भर झारखंड के निर्माण में ये बजट मददगार साबित होगा।

केंद्र सरकार के आर्थिक असहयोग के बावजूद, आंतरिक संसाधनों के माध्यम से झारखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। सामाजिक- आर्थिक रूप से महिलाएं कैसे सशक्त हो, इसको लेकर बजट राशि का एक बड़ा हिस्सा आधी आबादी को केंद्र में रख कर तैयार किया गया है।

साल 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे में झारखंड के महिला किसानों के

आर्थिक समृद्धि के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग प्रयासरत है।

इस बार महिला किसान खुशहाली योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत महिला किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर अद्यतन तकनीक की मदद दी जाएंगी। महिलाओं किसानों को आफलाइन एवं आनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म से जोड़ा जाएगा।

इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के लिए 25 करोड़ का बजटीय उपबंध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट भी तैयार किया गया है।

इस वर्ष 17 विभागों की योजनाओं में से महिलाओं से संबंधित लगभग 232 योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट तैयार किया गया है। जिसमें कुल 34 हजार 2 सौ 11 करोड़ 27 लाख रुपये की राशि का प्रबंध है।

राज्य की आर्थिक स्थिति खेती किसानी पर आधारित होने के कारण राज्य सरकार की प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना है। कृषि में समग्र विकास बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

अद्यतन आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार कृषि प्रक्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत गत तिमाही में 44.3 प्रतिशत से बढ़ कर 50.4 प्रतिशत हो गया है। बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना के लिए गत वित्तीय वर्ष के 95 करोड़ रुपये से बढ़ा कर वित्तीय वर्ष 2026-27 में 145 करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव है।

मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि राइस फैलो उपयोजना एवं जल निधि उपयोजना अंतर्गत सरकारी एवं निजी तालाबों का गहरीकरण या जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इस उपयोजना में 475 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट प्रस्ताव है।

कृषि समृद्धि योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी राज्य योजना है। सौर ऊर्जा से चालित इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है। कृषि यंत्र वितरण योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, पंप सेट, रीपर, ट्रांसप्लांटर आदि का वितरण किया जा रहा है।

इस योजना के लिए 80 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। झारखंड राज्य मिलेट्स मिशन 25 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। नकदी फसल विकास एवं विस्तार योजना के लिए 19 करोड़ 88 लाख रुपये बजट दिया गया है। राज्य उद्यान विकास योजना के तहत 245 करोड़ 80 लाख रुपये प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 481 करोड़ 35 लाख का प्रविधान किया गया है। गिरिडीह एवं सरायकेला में 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता की नई डेयरी तथा रांची में 20 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का मिल्क पाउडर प्लांट एवं उच्च क्षमता के मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए झारखंड मिल्क फेडरेशन को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़ का बजट है।

वित्तीय वर्ष 2026 -27 में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में लैंप्स पैक्स में कोआपरेटिव मार्केटिंग कांप्लेक्स सह सोलर पैनल आधारित कोल्ड रूम के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 162 करोड़ 20 लाख 90 हजार का बजटीय उपबंध किया गया है।

इसके अलावा 100 मीट्रिक टन क्षमता के 48 गोदाम, 500 मीट्रिक टन क्षमता के 24 गोदाम और 2500 मीट्रिक टन के 72 गोदाम का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस पर 160 करोड़ 26 लाख रुपये का बजट दिया गया है। तालाब एवं जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत 106 करोड़ रुपये प्रबंध किया गया है।

देवघर रेलवे स्टेशन पर लावारिश बैग में मिले हथियार समेत लाखों की चांदी, जांच में जुटी पुलिस

देवघर, एजेंसी। मंगलवार देर शाम देवघर स्टेशन पर कई हथियार और चांदी का खेप मिला. रेलवे पुलिस ने जमालपुर से देवघर आ रही एक ट्रेन में करीब दो किलो चांदी, दो देसी कट्टा, 2 देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए. घटना को लेकर आरपीएफ के इंस्पेक्टर शिव शंकर कुमार और देवघर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर दिनकर झा ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि रेलवे पुलिस को गस्ती के दौरान एक लावारिश बैग मिला. जिसमें ये सामान थे.

पुलिस ने लावारिश बैग की जैसे ही जांच पड़ताल शुरू की, तो कोई भी व्यक्ति उस बैग की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आया. काफी देर तक आसपास के लोगों से रेलवे पुलिस ने पूछताछ की. लेकिन किसी ने भी हथियार और चांदी से भरे बैग के बारे में नहीं बताया. जिसके बाद रेलवे पुलिस पूरे सामान को अपने कब्जे में लेकर रेलवे थाना ले गई.

अब सवाल यह उठ रहा है कि एक बैग में लाखों का चांदी और इतने हथियार किसने रखे और इसे कहां ले जाया जा रहा था. रेलवे पुलिस ने सभी हथियार और चांदी के खेप को जब्त कर नगर थाना के हवाले कर दिया. रेलवे पुलिस की तरफ से बताया गया कि मिली चांदी की कीमत करीब तीन से चार लाख रुपए है. वही हथियारों की भी कीमत करीब एक लाख रुपए आंकी गई है.

हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है. पुलिस की तरफ से तस्करी करने वालों की भी लिस्ट निकाली जा रही है. पुलिस द्वारा ऐसे अपराधियों की भी लिस्ट खंगाली जा रही है जो बाहर के शहरों में जाकर घटना को अंजाम देते हैं. देवघर रेलवे स्टेशन पर इस तरह हथियार के मिलने के बाद पुलिस किस निष्कर्ष पर निकलती है. क्योंकि देवघर रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है. ऐसे में जरूरी है कि देवघर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा सुनिश्चित हो.

झारखंड सरकार और पंजाब नैशनल बैंक के बीच सरकारी कर्मचारियों के वेतन खाता पैकेज पर हुआ समझौता

रांची , एजेंसी। झारखंड सरकार के कर्मचारियों के वेतन खाता पैकेज को लेकर एक और बैंक के साथ करार हुआ है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के बाद पंजाब नेशनल बैंक तीसरा बैंक है, जिसके साथ सरकार ने समझौता किया है. आज मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पंजाब नैशनल बैंक और झारखंड सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (रूप) हस्ताक्षर हो रहा है. पंजाब नैशनल बैंक आज राज्य सरकार के साथ एक नए अध्याय के रूप में जुड़ रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस के साथ-साथ राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों की आर्थिक लेन-देन की कड़ी में बैंक की अहम भूमिका होती है. वर्तमान समय में व्यवसाय, कृषि, ग्रामीण विकास सहित हरेक क्षेत्र में बैंक की बड़ी भूमिका होती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी कार्यों के साथ-साथ कई संस्थानों की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, इसी क्रम में आज राज्य सरकार एवं पंजाब नैशनल बैंक के बीच एक रूप साइन हुआ है. इससे पहले भी राज्य सरकार एवं अन्य

बैंकों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं और उक्त एमओयू के अनुरूप कार्यों को आगे बढ़ाया भी जा रहा है.

सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य से पंजाब नैशनल बैंक राज्य सरकार के साथ जुड़ी है, उस उद्देश्य और कर्तव्य को सफलता पूर्वक पूरा करेगी. राज्य सरकार एवं पंजाब नेशनल बैंक के बेहतर समन्वय का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित आम जनमानस को भी मिलेगा. मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से एमओयू हस्ताक्षर समारोह में उपस्थित पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों एवं कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी.

झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में बैंक के मंडल प्रमुख रांची अवधेश कुमार झा और वित्त विभाग के अधिकारी श्वेता सिंह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया. इस मौके पर पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक आशीष कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि इस बैंक में सैलरी एकांउट होने पर 10 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस सहित कई सुविधाएं दी जायेंगी. उन्होंने राज्य सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि बैंक द्वारा सरकारीकर्मी के लिए कई सुविधा दी गई हैं. इस मौके पर वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि इसके जरिए हमारे कर्मियों को इंश्योरेंस सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में देखा गया है कि दुर्घटना में जो सरकारी कर्मी मारे गए हैं, उनके परिजनों को एक करोड़ तक की सहायता राशि मिली है.

हजारीबाग में बाइक चोर गिरोह पर शिकंजा, एक साथ चोरी की 23 मोटरसाइकिल बरामद

हजारीबाग, एजेंसी। जिला पुलिस ने चोरी के 23 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं. वहीं एक चोर की गिरफ्तारी हुई है. हजारीबाग के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में चोरी किए गए मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद किया है. दरअसल, जिला में विगत दिनों में मोटरसाइकिल चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के लिए हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन के द्वारा सभी थाना एवं ओपी प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था. मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का उद्भेदन के लिए अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में एक स्कॉड का गठन किया गया.

हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापोकला में मोटरसाइकिल चोरी गिरोह के सदस्य बड़े पैमाने पर चोरी की मोटरसाइकिल की खरीद बिक्री होने वाली है. गठित छापेमारी दल के द्वारा कार्रवाई करते हुए एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया. चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया एवं पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ के दौरान अपना नाम सतीश प्रजापति बताया. आरोपी ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्र से मास्टर चाबी के माध्यम से वह मोटरसाइकिल चोरी करता है. उसकी निशानदेही पर उसके घर एवं घर के पीछे से कुल 23 चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया. गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में उसने सहयोगियों के नाम बताए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हजारीबाग स्कॉड्ड के द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

झारखंड बजट को भाजपा ने बताया दिशाहीन, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर साधा निशाना

रांची, एजेंसी। हेमंत सरकार द्वारा पेश बजट को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने दिशाहीन और तथ्यहीन बताया है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट रंगहीन है और खुशबू विहीन है. उन्होंने कहा कि 1.58 लाख करोड़ का बजट प्रस्ताव केवल गोल-मटोल आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण है. इसमें राज्य के विकास का कोई विजन नहीं दिखाई पड़ता है.

उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वित्त मंत्री आधे मन से भाषण पढ़ रहे थे. एक बार भी मुख्यमंत्री ने मेज थपथपा कर प्रोत्साहित नहीं किया. वित्त मंत्री इसे आदर्श बजट बता रहे थे. राज्य के सभी वर्गों युवा, किसान, महिला, उद्यमी से सलाह लेकर बनाया गया बजट बता रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्वयं कुछ दिनों पूर्व बयान दिया था कि बजट के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझसे पदाधिकारी कुछ पूछ नहीं रहे. आदित्य साहू ने कहा कि समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार किस दिशा में और कैसे चल रही है, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पर राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तरफ किसी के पैर पर झुकने से अच्छा अपने पैरों पर खड़ा होने की बात भी करते हैं. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार

को पानी पी-पी कर गाली देते हैं. उन्होंने कहा कि 1 लाख 36 हजार करोड़ के बकाए की बात खूब कर रहे हैं, लेकिन बार-बार पूछने के बाद भी आज तक राज्य की हेमंत सरकार नहीं बता पाई कि कब-कब का किस मद में बकाया है. आदित्य साहू ने कहा यह सरकार केवल इसे मुद्दा बनाकर अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास करती है. उन्होंने कहा कि सरकार इस बजट को बाल बजट बता रही है, लेकिन राज्य के हजारों लापता बच्चों की कोई चर्चा बजट में नहीं की गई है. इसी राज्य में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाया गया. ऐसे प्रभावित बच्चों के विषय में कोई घोषणा नहीं की गई है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि जेंडर बजट की बात कही गई है, लेकिन रोज-रोज राज्य में दुष्कर्म और हत्या हो रही है. ऐसे अपराध पर रोक के लिए कोई विशेष प्रावधान की बात नहीं की गई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पैसों की कोई कमी नहीं होने की बात की, लेकिन 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदने में यह सरकार पूरी तरह विफल रही. 2450 रुपये भी किसानों को नहीं मिले. इसे भी बिचौलिए खा गए.

उन्होंने कहा कि राज्य में डीएमएफटी फंड जो मोदी सरकार की देन है, लेकिन जिस प्रकार से पदाधिकारियों की सुख-सुविधा में इसका दुरुपयोग हुआ है वह जग जाहिर है. आदित्य साहू ने कहा कि इतना बड़ा घोटाला राज्य में हुआ है और इसकी जांच की कोई चर्चा नहीं हुई है. ऐसा लगता है जैसे खाता न बही, जो झामुमो-कांग्रेस कहे वही सही.

उन्होंने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री ने विभागों को पत्र लिखकर 10 हजार करोड़ का हिसाब नहीं मिलने और घोटाला की बात की है, लेकिन बजट में इसकी कोई चर्चा नहीं की है. उन्होंने पिछले बजट खर्च का ब्योरा देते हुए कहा कि अबतक 50% राशि ही राज्य सरकार खर्च कर पाई है. ऐसे में आखिर नए बजट प्रावधान का क्या मतलब.

माओवाद मुक्त होंगे चार जिले, झारखंड की जेलों में 5प्रतिशत जैमर, अफीम के बदले वैकल्पिक खेती

रांची, एजेंसी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11 हजार 38 करोड़ 53 लाख रुपये आवंटित किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य की जेलों में मोबाइल फोन के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष में 5जी सेल फोन जैमर तथा मोबाइल फोन डिटेक्टर का क्रय किया जाएगा और उसे सभी जेलों में लगाया जाएगा।

राज्य में माओवाद की समस्या के समाधान के लिए भी बजटीय उपबंध किया गया है। उन्होंने संभावना जताई है कि आगामी वित्तीय वर्ष में विशेष केंद्रीय सहायता मद से लगभग 60 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

इस राशि से राज्य में माओवाद प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम व माओवाद के प्रभाव से मुक्त तीन जिले बोकारो, चतरा व लातेहार के विकास कार्य होगा। इस राशि से इन चारों जिलों को माओवादियों के प्रभाव से मुक्त कराया जाएगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में झारखंड के विभिन्न शहरों की यातायात व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने व आवागमन को सुचारू बनाने के उद्देश्य से नए-नए यातायात थाने स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने अफीम प्रभावित जिलों की भी जानकारी दी और कहा कि अफीम उत्पादक जिले से अफीम की खेती के विनष्टीकरण के लिए अभियान चलाकर जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि अफीम प्रभावित इन जिलों में कृषकों को अफीम की खेती के बदले वैकल्पिक खेती के विकल्प दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्राकृतिक विपत्ति से निपटने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 900 करोड़ रुपये का प्रस्तावित बजट प्रस्तुत किया है।उन्होंने कहा कि इसमें राज्य आपदा मोचन निधि में 720 करोड़ रुपये व राज्य आपदा शमन निधि मद में 180 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र :21 एमवीआई की होगी नियुक्ति

रांची, एजेंसी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही निरसा विधायक अरुप चटर्जी ने नगरपालिक सेवा में नियुक्ति के मामले को उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि जेपीएससी से नियुक्ति नगरपालिका कर्मचारी सरकार के कर्मी हैं या नगर पालिका के।

वहीं उन्होंने नगरपालिका नियुक्ति नियमावली के मुद्दे को भी उठाया। इसके जवाब में मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि राज्य सरकार नियुक्ति नियमावली बना रही है। साथ ही यह स्पष्ट किया की। नियुक्त कर्मी नगरपालिका सेवा कैडर के कर्मचारी हैं।

सदन में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने मोटरयान निरीक्षक नियुक्ति को लेकर सवाल किया। जिसके जवाब में परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि सरकार ने 2023 में 46 पदों की अधियाचना की गई थी। अधियाचना के बाद हमने 40 मोटरयान निरीक्षक की नियुक्ति हमने की है। जिसमें तीन पहले से कार्यरत थे। 6 आउटसोर्स से लाए थे। वर्तमान में हमने 21 पद सृजित किए हैं। जिसपर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी।

विधानसभा में लोक निर्माण विभाग की लंबित निविदाओं का मुद्दा गरमाया रहा। विधायक हेमलाल मुर्मू और मथुरा महतो ने आरोप लगाया कि नियम के मुताबिक 180 दिनों के भीतर निविदाओं का निष्पादन होना चाहिए, लेकिन कई मामलों में एक साल से ज्यादा समय बीत चुका है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जवाब में मंत्री ने स्वीकार किया कि प्रक्रिया में देरी हुई है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की सभी लंबित निविदाओं को शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिया गया है। मंत्री ने साफ कहा कि 30 दिनों के भीतर यदि किसी निविदा पर निर्णय नहीं लिया गया, चाहे उसे पूरा किया जाए या रद्द तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सदन में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए तय 10 करोड़ रुपए की सीमा पर भी सवाल उठे। विधायक अमित कुमार ने कहा कि इस सीमा के कारण बड़े और जरूरी पुलों का निर्माण अटक रहा है। उनका तर्क था कि लागत बढ़ने के बावजूद विभागीय प्रावधान में बदलाव नहीं होने से विकास कार्य बाधित हो रहे हैं।

इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने समाधान सुझाते हुए कहा कि यदि ग्रामीण विकास विभाग के पास 10 करोड़ से अधिक लागत वाले पुलों के निर्माण का प्रावधान नहीं है, तो ऐसी योजनाओं को पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित कर दिया जाए। इससे तकनीकी और वित्तीय अड़चनें दूर होंगी और निर्माण कार्य में तेजी आएगी।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बकाया राशि भुगतान करने की मांग

पटना, एजेंसी। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत कथित तौर पर बकाया दो लाख रुपये के भुगतान की मांग को लेकर बुधवार को विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए राजद सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि राज्य सरकार महिलाओं के हक का पैसा देने से बच रही है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे राजद नेताओं ने कहा कि बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं योजना के तहत निर्धारित राशि मिलने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन भुगतान लंबित है। उनका कहना था कि सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया था, परंतु अब वादे से पीछे हट रही है। राजद विधायकों ने मांग की कि सभी पात्र महिलाओं को दो लाख रुपये का बकाया अविलंब जारी किया जाए और भुगतान प्रक्रिया की पारदर्शी समीक्षा कराई जाए। विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो सदन के भीतर और बाहर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हालांकि योजना से संबंधित भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत चल रही है और पात्रता सत्यापन के बाद ही राशि जारी की जाती है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक करार दिया है।

ललन सिंह का राहुल गांधी पर वार- परिपक्व बनिए

पटना। एआई समिट में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद केंद्र सरकार के मंत्री ललन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को 'तानाशाही प्रवृत्ति' बताया था। साथ ही अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील को देशहित के खिलाफ करार दिया। उनके बयान के बाद सत्ता और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी के बयान को अपरिपक्व बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश सर्वोपरि है। ललन सिंह ने आरोप लगाया कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस तरह का विरोध देश की छवि खराब करता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक कार्यक्रम के दौरान इस प्रकार का प्रदर्शन अनुचित है। साथ ही इसे देशहित के खिलाफ बताया। राहुल गांधी ने ङ्क पर पोस्ट कर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कार्रवाई पर गर्व जताया। राहुल ने ट्रेड डील को किसानों और टेक्सटाइल उद्योग के लिए नुकसानदेह बताया।इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच बयानबाजी और तेज होने के संकेत हैं। एक ओर सरकार विरोध को देश की छवि से जोड़ रही है। वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र की आवाज बता रहा है। एआई समिट के मंच से उठी यह बहस अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुकी है।आने वाले दिनों में इस पर और तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया संभव है।

चतरा एयर एम्बुलेंस हादसा, पटना के सचिन मिश्रा की मौत

पटना, एजेंसी। चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश के दौरान पटना के सचिन मिश्रा की भी मौत हो गई। सचिन उस एयर एम्बुलेंस में बतौर नर्सिंग स्टाफ मौजूद थे। हादसे से चंद घंटे पहले ही उन्होंने अपने घर पर बीमार मां से फोन पर बात कर हाल-चाल पूछा था। बेटे की मौत की खबर सुनते ही मां की तबीयत बिगड़ गई। परिजन बताते हैं कि वह बार-बार बेहोश हो जा रही थीं। सचिन चार भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। पिता का निधन वर्ष 2005 में हो गया था। इसके बाद बड़े भाइयों ने ननिहाल पक्ष के सहयोग से परिवार की जिम्मेदारी संभाली। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद पूजा-पाठ कर सचिन को पढ़ाया-लिखाया गया। परिवार फिलहाल राजीव नगर में रहता है, जबकि पैतृक घर सिवान जिले के तिलकथू थाना हसनपुरा में है। सचिन की मां ने बताया कि, उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसके चलते बेटा छुट्टी लेकर उनसे मिलने घर आना चाहता था, लेकिन अस्पताल के कर्मियों की ओर से छुट्टी नहीं दी गई। तीन दिन पहले किसी पेशेंट को लेकर पटना एयरपोर्ट भी आया था। वहां से वह मिलने आ रहा था, लेकिन हॉस्पिटल के कर्मियों ने उसे एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। मृतक की बहन ने बताया कि, दोपहर में मां से सचिन की बात हुई थी। मां ने दवा के रिएक्शन की जानकारी दी, जिस पर सचिन ने एक डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। इसके बाद शाम से उनका फोन बंद हो गया। लगातार कॉल करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका ।मृतक की बहन ने बताया कि, दोपहर के वक्त सचिन की बात मां से हुई थी। मां ने उसे दवा रिएक्शन के बारे में बताया था। तब उसने एक डॉक्टर के बारे में सजेस्ट किया और बोला वहां दिखा लो। इसके बाद शाम से उसका कॉल लगना बंद हो गया। लगातार हम लोग कॉल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था। मेरा भाई मां को देखने के लिए बेचैन था। छुट्टी मांग रहा था, लेकिन उसके अस्पताल के कर्मियों ने छुट्टी नहीं दी। बहन का कहना है कि सचिन मां को देखने के लिए परेशान थे और छुट्टी मांग रहे थे। अगर उन्हें छुट्टी मिल जाती, तो शायद यह हादसा नहीं होता। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

बिहार में लागू होगा गुजरात का सफल सहकारी मॉडल,

जैविक खेती और ग्रामीण विकास को बढ़ावा

पटना, एजेंसी। सहकारिता विभाग द्वारा गुजरात में सफल सहकारी समितियों के माडल को लागू कराने की तैयारी हो रही है। इसके लिए विभागीय स्तर से सहकारी समितियों के 50-50 लोगों की टीम गुजरात के दौरे पर भेजी जाएगी। ये टीमें गुजरात में कार्यरत सहकारी समितियों के कार्यों का अवलोकन और अध्ययन करेंगी।

बिहार में 28 हजार सहकारी समितियां हैं जिनके अध्यक्षों व सचिवों के अलावा सदस्यों की अलग-अलग टीम बनाकर गुजरात भेजी जाएगी। वहां से लौटने के बाद संबंधित सहकारी समितियों को गुजरात में कार्यरत समितियों की तरह कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।

डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि गुजरात में सामूहिक जैविक खेती जैसे नवाचार सफल माडल साबित हुआ है। गुजरात में सहकारी समितियां किसानों को सीधे जोड़कर, उन्हें जैविक खेती का प्रशिक्षण, प्रमाणित जैविक इनपुट (बीज, खाद) और उत्पाद की अच्छी मार्केटिंग सुनिश्चित करके जैविक खेती को बढ़ावा दे रही हैं।

भारत ऑर्गेनिक जैसी संस्थाएं और डेयरी, गोबर से खाद बनाकर और फसलों की जैविक खरीद-बिक्री के लिए जीयूजेको और अमूल जैसे नेटवर्क का उपयोग करती हैं। जब गुजरात से ऐसी सहकारी समितियों का कार्यानुभव लेकर टीम लौटेगी तब जैविक खेती में गुजरात मॉडल का सफल प्रयोग सहकारी समितियों के सहयोग से किया जाएगा।

जैविक खेती में नवाचार दिखाने वाले किसानों की ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। जैविक उत्पादों की खरीद और बेहतर मूल्य से लेकर बाजार उपलब्ध कराने की कार्य योजना बनायी जाएगी। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को जैविक खेती में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।

ऐसे उत्पादों को पंजीकरण कराने से लेकर प्रमाणन की व्यवस्था भी होगी। गुजरात के भरूच जैसे क्षेत्रों में केले के तने से रेशा और वर्मी कम्पोस्ट जैसे जैविक उत्पाद बनाकर आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह के कार्य उत्तर बिहार के केला उत्पादन वाले इलाकों में बखूबी संभव है।

इसी तरह गुजरात में अमूल जैसी सफल सहकारी संस्थाओं की कार्यशैली ने वहां ग्रामीण आजीविका को नई ताकत दी है। यह कार्य बिहार में भी सहकारी समितियों से होगा।

सहकारिता विभाग ग्रामीण इलाकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्थानीय युवकों को रोजगार के अवसर देने पर भी काम कर रहा है। इसके लिए टैक्सी सर्विस स्कीम भी लॉन्च करने की योजना बन रही है। इससे स्थानीय लोगों को सीधे रोजगार प्रदान करने की मदद मिलेगी। गुजरात में महिलाओं द्वारा संचालित दुग्ध समितियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

यही प्रयोग बिहार के सभी गांवों में महिलाओं द्वारा दुग्ध समितियों के संचालन में होगा।हर गांव में दुग्ध सहकारी समिति गठित की जा रही है। प्रोटीन कंसन्ट्रेट पाउडर प्लांट जैसी नई इकाईयां लगायी जाएंगी। जाहिर है, इससे डेयरी क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे।

डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाने से भी सहकारी समितियों को ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। इससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका कम होगी। सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता लाने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि सहकारी समितियों के सदस्य किसानों का भरोसा और मजबूत हो।

सरकार का लक्ष्य है कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी की जाए। इसके लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और नई योजनाओं को लागू करने पर फोकस किया जा रहा है।

मुंगेर में 'बच्चा चोरी' की साजिश नाकाम, दादी बनी ढाल, केमिकल छिड़क फरार हुईं संदिग्ध युवतियां

मुंगेर, एजेंसी। मुंगेर जिले में बच्चा चोरी की अफवाहों के बीच मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज घटना ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी। असरगंज प्रखंड के चोर गांव पंचायत अंतर्गत बिंद टोला में घर के बरामदे में सो रहे दो मासूम बच्चों को उठाने की कोशिश की गई। दादी की सतर्कता से बच्चों की जान बच गई, लेकिन केमिकल छिड़ककर फरार हुईं संदिग्ध युवतियों ने इलाके में दहशत फैला दी है।

जानकारी के अनुसार, 65 वर्षीय सीमा देवी अपने छह वर्षीय पोते रितेश कुमार और दस वर्षीय पोती रागिनी के साथ मच्छरदानी लगाकर बरामदे में सो रही थीं। देर रात दो अज्ञात युवतियां दबे पांव वहां पहुंचीं और मच्छरदानी हटाकर बच्चों को खींचने लगीं। आहट से सीमा देवी की नींद खुल गई तो उन्होंने शोर मचा दिया। शोर सुनते ही दोनों युवतियां घबरा गईं। आरोप है कि भागने के दौरान उन्होंने बुजुर्ग महिला पर किसी अज्ञात केमिकल का छिड़काव कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गईं। केमिकल के असर से सीमा देवी बेहोश होकर गिर पड़ीं। परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्हें अचेत अवस्था में पाया। तुरंत डायल 112 पर सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, असरगंज में भर्ती कराया, जहां करीब दो घंटे बाद उन्हें होश आया। होश में आने के बाद सीमा देवी ने पूरी घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी की अफवाहें फैल रही थीं, जिससे लोग पहले से ही भयभीत थे। इस घटना ने आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में पूछताछ जारी है।

शादी की खुशियां मातम में बदलीं, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, दो घरों के इकलौते चिराग बुझे

पूर्णिया, एजेंसी। पूर्णिया जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सोमवार देर रात बायसी थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। दोनों युवक एक शादी समारोह (बारात) से लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना से दो गांवों में मातम पसर गया है और दोनों परिवारों के इकलौते वारिस हमेशा के लिए छिन गए।

हादसा बायसी थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग स्थित पूरब चौक के पास हुआ। मृतकों की पहचान डगरुआ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बरसौनी निवासी अरुण मंडल के पुत्र बादल मंडल (19 वर्ष) और कोचेली निवासी अरविंद विश्वास के पुत्र बादल कुमार (22 वर्ष) के रूप में की गई है।

परिजनों के अनुसार, दोनों दोस्त सोमवार शाम एक करीबी की बारात में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। देर रात लौटते समय उनकी बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। पूरब चौक के समीप चालक संतुलन खो बैठा और बाइक सीधे कंक्रीट के डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक उछलकर सड़क पर गिर पड़े। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।

सबसे दुखद पहलू यह है कि बादल मंडल और बादल कुमार दोनों अपने-अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। बादल कुमार अपने पिता के साथ कारीगरी का काम कर परिवार का सहयोग करता था, जबकि बादल मंडल पूर्णिया में मजदूरी कर घर का भरण-पोषण करता था। घटना की सूचना मिलते ही दोनों गांवों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है।

सूचना मिलते ही बायसी थानाध्यक्ष शिवकुमार पासवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए पूर्णिया जीएमसीएच भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण बाइक की तेज रफ्तार प्रतीत हो रहा है। क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया गया है।

बिहार में दनादन एक्शन, सर्वे अमीन से लेकर घूसखोर आपूर्ति पदाधिकारी गिरफ्तार

सुपौल/समस्तीपुर , एजेंसी। बिहार में निगरानी विभाग का एक्शन लगातार जारी है. राज्य के विभिन्न जिलों में घूसखोर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी की गिरफ्तारी हो रही है. इसी कड़ी में सुपौल और समस्तीपुर में दबिश दी गई. इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. सुपौल में सर्वे अमीन गिरफ्तार : निर्मली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 स्थित नाग मंदिर के पास मंगलवार को निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सर्वे अमीन विक्रम कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.

50 हजार मांगी गई थी रिश्वत : प्राप्त जानकारी के अनुसार, मरौना अंचल क्षेत्र के खोरमा गांव निवासी रिटायर्ड दफादार जय नारायण यादव से जमीन सर्वे के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही थी. आरोप है कि सर्वे अमीन विक्रम कुमार ने कुल 50 हजार रुपये की मांग की थी. शिकायतकर्ता द्वारा रकम दो किश्तों में देने की सहमति के बाद पहली किश्त के रूप में 20 हजार रुपये देने के लिए मंगलवार को नाग मंदिर के पास बुलाया गया था. इससे पहले जय नारायण यादव ने पूरे मामले की शिकायत निगरानी विभाग में दर्ज कराई थी.

जाल बिछाया और दबोचा : शिकायत की सत्यता की जांच के बाद पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही सर्वे अमीन ने रिश्वत की राशि ली, टीम ने उसे मौके पर ही धर दबोचा. स्थानीय लोगों ने निगरानी विभाग की इस सख्त कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी.

निगरानी विभाग, पटना के पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र कुमार का कहना है कि ''आरोपी सर्वे अमीन को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे पटना ले जाया जा रहा है, जहां आगे की पूछताछ और कार्रवाई की जाएगी. आरोपी सर्वे अमीन निर्मली नगर के वार्ड नंबर1 में बद्री नारायण साह के मकान में किराए पर रह रहा था. वहीं रुपये लेकर रिटायर्ड दफादार को बुलाया गया था.''

समस्तीपुर में आपूर्ति पदाधिकारी गिरफ्तार : दलसिंहसराय में निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए विद्यापतिनगर एवं उजियारपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजेश भगत को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी राजेश कुमार को निगरानी ने दलसिंहसराय स्थित काली चौक के निकट किराया के आवास से गिरफ्तार किया है.

दरअसल, मनियारपुर पंचायत के पीडीएस डीलर राम एकबाल सिंह ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजेश भगत पर जन वितरण प्रणाली अंतर्गत अतिरिक्त खाद्य आवंटन बढ़ाने के एवज में रिश्वत की मांगने का आरोप लगाया गया था. 30 हजार रिश्वत की मांग की गई थी. डीलर से पहले 10 हजार रुपये देने को कहा गया. पीड़ित की शिकायत के बाद एक्शन में आई निगरानी की टीम ने जाल बिछाया. पैसे के साथ डीलर दलसिंहसराय स्थित आपूर्ति पदाधिकारी के पास पंहुचता है. वहीं पहुंची टीम रंगेहाथ उसे धर दबोचती है. गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम आरोपी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अपने साथ पटना लेकर चली गयी. निगरानी के डीएसपी अखिलेश कुमार ने कहा कि डीलर राम इकबाल की शिकायत पर निगरानी थाने में मामला दर्ज किया गया था.

नालंदा में मस्जिद के पास डीजे बजाने पर झड़प: पुलिस ने कराया मामला शांत

नालन्दा, एजेंसी। नालंदा के मोगलकुआं इलाके में मंगलवार की रात बारात में डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गई। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामला तुरंत शांत करा लिया गया। एहतियात के तौर पर इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है।

जानकारी के अनुसार, सोहसराय थाना क्षेत्र के बॉली पर से होते हुए एक बारात मोगलकुआं मस्जिद के पास से गुजर रही थी। बारात में डीजे बज रहा था। उसी समय मस्जिद में दूसरे समुदाय के लोग नमाज अदा कर रहे थे। नमाजियों ने डीजे की आवाज पर आपत्ति जताई और उसे बंद करने को कहा। इसी बात को लेकर बारात में शामिल लोगों और वहां मौजूद दूसरे पक्ष के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस हल्की झड़प में तब्दील हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।

घटना के वक्त मौके पर मौजूद 'डायल 112' की पुलिस टीम ने स्थिति की नजाकत को भांपते हुए तुरंत वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आनन-फानन में कई थानों की पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर अलग किया और मामले को शांत कराया। पुलिस इलाके में गश्त कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

सोहसराय थानाध्यक्ष मुकेश कुमार मुकेश ने बताया कि मस्जिद के पास से एक बारात गुजर रही थी। डीजे पर गाना बजाने को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद विवाद की स्थिति बनी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करा लिया है। किसी तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल कैंप कर रहा है।

केंद्र सरकार की बिहार को बड़ी सौगात, पुनारख-किउल तीसरी-चौथी लाइन के लिए 2,268 करोड़ रुपये मंजूर

पटना, एजेंसी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बताया कि पुनारख और किउल के बीच तीसरी एवं चौथी रेल लाइन परियोजना को केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना का कुल निवेश 2,668 करोड़ रुपये है, जिसमें पुनारख-किउल खंड (लगभग 50 किलोमीटर) के निर्माण के लिए 2,268 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना को तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत डिजाइन की गई यह परियोजना माल और यात्री ट्रेनों के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर भीड़भाड़ कम करेगी और रेल सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पटना और लखीसराय जिलों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

डिप्टी सीएम चौधरी ने इस परियोजना को बिहार के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी, ट्रेनों की समयपालन क्षमता बढ़ेगी तथा व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि निर्धारित समय में परियोजना पूरी होने पर यह बिहार की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी।

उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बिहार की ओर से हृदयपूर्वक धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि बिहार में रेलवे के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। वर्तमान में राज्य में 14 वंदे भारत और 21 अमृत भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, और हाल ही में वाराणसी-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को भी मंजूरी मिली है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कुल 9,072 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें पुनारख-किउल तीसरी-चौथी लाइन के अलावा गोंडिया-जबलपुर रेल लाइन दोहरीकरण और गम्हरिया-चंदिल तीसरी-चौथी लाइन परियोजनाएं भी शामिल हैं।

जनगणना 2027, बिहार में अधिकारी एक्शन मोड में

पटना, एजेंसी। भारत की जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से पटना में राज्यस्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और नगर आयुक्त शामिल हुए. सम्मेलन का उद्देश्य आगामी जनगणना प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देना था, ताकि आंकड़ों का संग्रहण पूरी तरह सटीक और पारदर्शी तरीके से किया जा सके.

मुख्य सचिव ने की अध्यक्षता : सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि जनगणना की सटीकता पर ही राष्ट्र और राज्य की नीतियों का निर्माण निर्भर करता है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाएं जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही तैयार की जाती हैं. ''ऐसे में यदि आंकड़ों में कोई भी त्रुटि होती है तो उसका सीधा असर नीति निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ता है. इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे इस कार्य को पूरी गंभीरता से करें.''

17 अप्रैल से सेल्फ काउंटिंग की सुविधा : सम्मेलन में बताया गया कि 17 अप्रैल से नागरिकों के लिए सेल्फ काउंटिंग की सुविधा शुरू की जाएगी. इसके तहत लोग स्वयं अपनी जानकारी डिजिटल माध्यम से दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद 2 मई से प्रशिक्षित गणना कर्मी घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे.

जनगणना में 33 प्रश्न : इस बार जनगणना में कुल 33 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिनके माध्यम से परिवार की संरचना, आवासीय स्थिति, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से जुड़ी जानकारियां एकत्र की जाएंगी. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करें और समयबद्ध तरीके से सभी तैयारियां पूरी करें.

जनगणना से भविष्य की योजनाएं तय होती हैं : मुख्य सचिव ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन भर नहीं है, बल्कि यह भविष्य की योजनाओं की नींव है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे तकनीकी व्यवस्था को मजबूत करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर डेटा एंट्री में लापरवाही न हो. साथ ही यह भी कहा गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज होने वाली जानकारियों की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी.

आम जन में जागरूकता का निर्देश : सम्मेलन में यह भी बताया गया कि जनगणना कार्य को लेकर आम जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है. इसके लिए जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोग बिना किसी हिचक के अपनी सही जानकारी उपलब्ध करा सकें. अधिकारियों से कहा गया कि वे स्थानीय स्तर पर पंचायतों, नगर निकायों और अन्य संस्थाओं के सहयोग से लोगों को यह समझाएं कि जनगणना में दी गई जानकारी का उपयोग केवल नीतिगत और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा : प्रशिक्षण सम्मेलन में तकनीकी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों को डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल, प्रश्नावली भरने की प्रक्रिया और त्रुटियों से बचने के तरीकों की जानकारी दी गई. इसके अलावा यह भी बताया गया कि फील्ड स्तर पर किसी भी समस्या की स्थिति में त्वरित समाधान के लिए अलग से हेल्प डेस्क और निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी.

ओबरा विद्यालय के 40 छात्र-छात्राएं बोधगया रवाना

औरंगाबाद, एजेंसी। औरंगाबाद के ओबरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय से 40 छात्र-छात्राओं का एक दल मंगलवार सुबह शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए बोधगया रवाना हुआ। यह यात्रा मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना के तहत आयोजित की गई है।

सुबह ठीक 8:00 बजे विद्यालय परिसर से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विद्यार्थियों में इस शैक्षणिक यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। परिभ्रमण दल के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतेंद्र प्रसाद, शिक्षिका किरण कुमारी, मिशा भारती, मीनू कुमारी, शिक्षक जगदीश चौधरी और शिक्षा सेवक राजू कुमार मौजूद रहे। ये सभी बच्चों के मार्गदर्शन एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

ओबरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) मोहम्मद यूनिस सलीम और विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक सह पेंशनर समाज के सचिव त्रिवेणी पांडे ने संयुक्त रूप से बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर बीडीओ मोहम्मद यूनिस सलीम ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक परिभ्रमण से बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है, जिससे उनके ज्ञान और दृष्टिकोण का विस्तार होता है।

संक्षिप्त समाचार

कुत्ते के हमले से घायल बच्ची के चेहरे की सर्जरी

मेरठ, एजेंसी। बागपत की ढाई वर्षीय बच्ची सारा पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। उसके चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं। इस घटना के बाद उसे तत्काल मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सफल प्लास्टिक सर्जरी की। डॉ. भानु प्रताप सिंह एवं उनकी टीम ने नए प्रोटोकॉल के तहत गंभीर घावों को ठीक करने के साथ चेहरे को सामान्य आकार में लाया गया तथा घाव के निशान को न्यूनतम किया गया। समय पर इलाज और विशेषज्ञ सर्जरी से बच्ची का चेहरा सफलतापूर्वक सुधारा गया है। डॉ. भानु प्रताप सिंह ने बताया कि कुत्ते के काटने से हुए गंभीर घावों का अब उन्नत सर्जरी और कॉस्मेटिक तकनीकों से इलाज संभव हो गया है, जिससे पीड़ितों को सामान्य जीवन मिल सकता है। मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर.सी. गुप्ता ने डॉ. सिंह एवं टीम को बधाई दी। उन्होंने कुत्ते के काटने पर तत्काल सावधानियां बरतने की सलाह दी। घाव को साबुन-पानी से अच्छी तरह धोएं और जल्द से जल्द एंटी-रेबीज टीकाकरण कराएं। आजकल आवारा कुत्तों के हमले बढ़ रहे हैं, ऐसे में समय पर चिकित्सा सहायता महत्वपूर्ण है।

तीन मार्च को लगेगा खग्रास चंद्रग्रहण, 50 मिनट दिखेगा दृश्य

गोरखपुर एजेंसी। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, मंगलवार तीन मार्च को खग्रास चंद्रग्रहण लगेगा। यह ग्रहण खंडग्रास चंद्रग्रहण के रूप में दिखाई देगा। विभिन्न स्थानों पर चंद्रोदय के समय चंद्रमा ग्रहण से ग्रस्त रहेगा और मोक्ष के समय तक ही ग्रहण दृश्य होगा। ग्रहण का स्पर्श और प्रारंभ भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन खंड चंद्रग्रहण का मोक्ष 50 मिनट तक देखा जा सकेगा। पंडित शरद चंद्र मिश्र के अनुसार, जिले में चंद्रोदय मंगलवार को शाम पांच बजकर 57 मिनट पर होगा, उसी समय चंद्रमा ग्रस्त अवस्था में रहेगा। ग्रहण का मोक्ष शाम छह बजकर 47 मिनट पर होगा। इस प्रकार यहां ग्रहण लगभग 50 मिनट तक ही दृश्य रहेगा। यह ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में घटित होगा। फाल्गुन मास में पड़ने वाला यह चंद्रग्रहण नृत्य, संगीत और कला से जुड़े लोगों, श्रेष्ठ स्त्रियों, सैनिकों तथा तपस्वियों के लिए कष्टकारक प्रभाव दे सकता है। मंगलवार को घटित होने के कारण सामाजिक अशांति की आशंका भी व्यक्त की गई है। वहीं गोरखनाथ मंदिर संस्कृत विद्यापीठ के सहायक आचार्य डॉ. प्रांगेश कुमार मिश्र के अनुसार, ग्रहण का सूतक काल सुबह 06:20 पर लगेगा, इसके बाद मंदिरों के कपाट बंद हो सकते हैं। उनका कहना था कि ग्रहण के दौरान भगवान की पूजा-अर्चना करना चाहिए। मंत्र जाप भी काफी लाभदायक होता है।

सीएम योगी ने विदेशी दिग्गजों को भेंट की बनारसी विरासत

वाराणसी ब्यूरो। काशी की प्राचीन गलियों से निकलकर गुलाबी मीनाकारी की कलाकृतियां अंतरराष्ट्रीय फलक पर पहुंच गई हैं। सिंगापुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने पारंपरिक धरोहरों में शामिल ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट) उत्पादों को विशेष उपहार के तौर पर विदेशी प्रतिनिधियों को भेंट किया। यूपी सरकार की ओडीओपी योजना के तहत प्रत्येक जिलों की पारंपरिक विशेषता को इंटरनेशनल मंच पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बनारस की गुलाबी मीनाकारी भी इनमें से एक है। वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी अपनी अनूठी शिल्प शैली के लिए लोकप्रिय है। चांदी और सोने पर बारीक नक्काशी के बाद तप कर गुलाबी मीनाकारी का गुलाबी रंग विश्व पटल के हैंडीक्राफ्ट के मानचित्र पर गहरी छाप छोड़ रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त गुलाबी मीनाकारी के हस्तशिल्पी कुंज बिहारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से विदेशी प्रतिनिधियों को ये उत्पाद उपहार में देना राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देने जैसा है। यह विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा और संभावनाओं से परिचित कराने का माध्यम बन रहा है। कुंजबिहारी ने बताया कि हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री गुलाबी मीनाकारी के उत्पाद स्वयं लेकर जापान और सिंगापुर के दौरे पर गए हैं। गुलाबी मीनाकारी को जीआई टैग प्राप्त है।

खाद्य सामग्रियों में मिलावट के सबूत विभाग में सड़ रहे...चूहे कुतर रहे सैंपल

गोरखपुर, एजेंसी। मिलावटखोरी पर कार्रवाई के लिए दुकानों से लिए गए खाद्य सामग्रियों के सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय में रख-रखाव के अभाव में सड़-गल रहे हैं। इन्हें सुरक्षित रखने के इंतजाम नहीं हैं। कुछ सैंपल को तो चूहे कुतर कर खा जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, साक्ष्य सुरक्षित नहीं रहने पर आरोपियों को इसका फायदा मिल सकता है। कलक्ट्रेट परिसर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग का दफ्तर है। इसी दफ्तर के एक कमरे में मिठाई, नमकीन, चिप्स और पापड़ के सैंपल रखे गए हैं। इसके अलावा गैलरी में रखी आलमारी और बड़े बक्शे में भी 20 से 25 साल पुराने सैंपल हैं। इनमें से कई मामलों में अभी मुकदमा चल रहा है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से रखे गए सैंपल को देखा ही नहीं गया। मिठाई और नमकीन वाले सैंपल खुले में रखे गए हैं, गत्ते को कुतर कर उसमें रखे नमूने चूहे खा रहे हैं।

होली पर मिलावट का बाजार

आटा, दाल, दूध से लेकर मसाले तक नहीं शुद्ध; पनीर तो ना ही लें

आगरा, एजेंसी। होली से पहले खाद्य सुरक्षा प्रशासन की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दूध, घी, पनीर, तेल और मसालों के बड़ी संख्या में नमूने फेल मिले हैं, जिससे बाजार में मिलावटखोरी का जाल उजागर हुआ है।

होली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट का काला साया मंडरा रहा है। मिलावटखोर जहर परोस रहे हैं। यह खुलासा खाद्य सुरक्षा प्रशासन की सैंपलिंग रिपोर्ट से हुआ है। बाजार में बिक रहे खुले दूध से लेकर मसाले तक स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। पनीर और घी के सबसे ज्यादा नमूने फेल हुए हैं।

शासन के निर्देश पर सोमवार को पांच तेल कंपनियों पर छापेमारी में मिलावट की आशंका पर 62 हजार लीटर सरसों का तेल और रिफाइंड जब्त किया गया। यह पिछले पांच साल में सबसे बड़ी कार्रवाई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर भी इससे सवाल उठे हैं।

आगरा उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के महानगर अध्यक्ष नरेश पांडेय का कहना है कि 70 प्रतिशत व्यापारी खाद्य पदार्थों के कारोबार से जुड़ा है। खाद्य सुरक्षा के स्पष्ट मानक नहीं हैं, जिसका फायदा उठाकर खाद्य अधिकारी अवैध वसूली करते हैं। सिर्फ त्योहार पर कार्रवाई की याद आती है। पूरे साल विभाग आंखें बंद रखता है।

लगाएंगे भारी जुर्माना : जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की नियमित समीक्षा होगी और मिलावटखोरी के विरुद्ध अभियान चलेगा। अधिकारियों की संलिप्तता पर सख्त कार्रवाई होगी। जिन व्यापारियों के नमूने फेल हुए हैं। उन पर भारी जुर्माना लगाने के साथ गंभीर मामलों में विधिक कार्रवाई की जाएगी।

होली पर अतिरिक्त बसें चलाएगा परिवहन निगम

मेरठ , एजेंसी। इस होली पर बसों में मारामारी रहेगी। सभी यात्रियों को बसों में सीट मिलेंगी।

इस बार परिवहन निगम ने होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। मेरठ परिक्षेत्र के बस अड्डों से 28 फरवरी से नौ मार्च तक अतिरिक्त बसें चलेंगी। चालक, परिचालक और अन्य कर्मचारियों को अभी अतिरिक्त कार्य करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। निगम का दावा है कि इस बार होली पर पर्याप्त बसें रहेंगी और लोग सीट पर बैठकर यात्री करेंगे। सोहराबगेट एवं मेरठ डिपो प्रभारी आसिफ अली ने बताया कि दोनों डिपो की बसों का बेड़ा बढ़ा दिया गया है, ताकि त्यौहार पर यात्रियों को बस आसानी से मिल सके।

ये है चालक व परिचालकों को प्रोत्साहन योजना : परिवहन निगम के जो चालक और परिचालक 10 दिन में 3000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे उनको 4500 रुपये का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। प्रतिदिन 450 रुपये के हिसाब से होगा। 9 दिन की ड्यूटी पर 2700 किलोमीटर पूरे करने पर 3600 रुपये मिलेंगे। निर्धारित किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर 55 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त दिए जाएंगे। कार्यशाला कार्मिकों और आउटसोर्स कर्मियों को भी लाभ मिलेगा। 10 दिन की ड्यूटी पर उन्हें 2100 रुपये और 9 दिन की ड्यूटी पर कर्मियों को 1800 रुपये दिए जाएंगे।

होली में तीन स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, दो दिल्ली के लिए

गोरखपुर। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए तीन होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल, पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार टर्मिनल और गोमतीनगर-मालतीपाटपुर के बीच चलाई जाएंगी।05575 सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल होली स्पेशल 11 मार्च को सहरसा से रात 8:00 बजे चलेगी। दूसरे दिन गोरखपुर से सुबह 09:50 बजे छूटकर आनंद विहार टर्मिनल देर रात 01:05 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 05576 आनंद विहार टर्मिनल-सहरसा होली स्पेशल 10 एवं 17 मार्च को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 05:15 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर से शाम 7:40 बजे छूटकर दूसरे दिन सहरसा से सुबह 10:30 बजे पहुंचेगी।05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार टर्मिनल होली स्पेशल 06 से 15 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को पूर्णिया कोर्ट से शाम 4:30 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन गोरखपुर से सुबह 09:50 बजे छूटकर आनंद विहार टर्मिनल देर रात 01:05 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 05580 आनंद विहार टर्मिनल-पूर्णिया कोर्ट होली स्पेशल 08 से 16 मार्च तक प्रत्येक रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 05:15 बजे चलकर गोरखपुर से शाम 7:40 बजे छूटकर दूसरे दिन पूर्णिया कोर्ट दोपहर 1:45 बजे पहुंचेगी। 05064 गोमतीनगर-मालतीपाटपुर साप्ताहिक होली स्पेशल 26 फरवरी से 26 मार्च तक प्रत्येक वृहस्पतिवार को गोमतीनगर से शाम 6:55 बजे चलकर दूसरे दिन गोरखपुर से रात 12:15 बजे छूटकर मालतीपाटपुर देर रात 03:30 बजे पहुंचेगी।

प्रदेश में घोषित हुआ प्राइमरी स्कूलों की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम, 1.52 करोड़ विद्यार्थी देंगे इग्जाम

लखनऊ, एजेंसी। 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों के 1.52 करोड़ विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 16 मार्च से शुरू होंगी। इसका परिणाम 30 मार्च को अभिभावकों की उपस्थिति में जारी किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, कक्षा एक से आठ तक की वार्षिक परीक्षाएं 16 से 20 मार्च के बीच आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार कराकर बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को दिया जाएगा। बीएसए इसका मुद्रण कराकर विद्यालयों में वितरण कराएंगे। कक्षा एक की वार्षिक परीक्षा मौखिक होगी। कक्षा दो से पांच की परीक्षा लिखित व मौखिक दोनों माध्यम से होगी। दो व तीन में इसका अधिभार 50-50 फीसदी होगा।

वहीं, कक्षा चार व पांच में क्रमशः 70 व 30 का होगा। लिखित परीक्षा 50 नंबर की होगी। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी जबकि मौखिक परीक्षा के लिए प्रधानाध्यापक आवश्यकतानुसार समय तय करेंगे। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने निर्देश दिया है कि मूल्यांकन कार्य शुचितापूर्ण तरीके से कराते हुए 30 मार्च को परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों को अभिभावकों की उपस्थिति में दिया जाएगा।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले- शंकराचार्य जैसी संस्था को समाप्त करने का रचा जा रहा इतना बड़ा षड्यंत्र

वाराणसी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शंकराचार्य जैसी संस्था को समाप्त करने का इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह मामला भारत के दुर्लभतम मामलों में प्रवेश कर रहा है। इस पर पूरे देश को ध्यान देने की जरूरत है। अगर मुझ पर लगाए गए आरोप साबित होते हैं तो फिर शंकराचार्य को इतना बड़ा दंड देना चाहिए जिसे सदियों तक याद रखा जाए। लेकिन अगर आरोप साबित नहीं होते हैं तो शिकायतकर्ता के लिए भी वैसा ही दंड होना चाहिए।

ये बातें मंगलवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पत्रकारों से कहीं। उन्होंने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई भी आया और शिकायत करके निकल गया। शंकराचार्य ने एक फोटो दिखाते हुए कहा कि इनका नाम अजय पाल शर्मा है। इस समय इनके अधीन ही जांच चल रही है। इनके साथ दिख रहा व्यक्ति शिकायतकर्ता हिस्ट्रीशीटर है और वह पुलिस के बड़े अफसर के साथ केक काटकर बर्थडे मना रहा है। हमें यह तस्वीर कुछ लोगों ने भेजी है और अब लोग ही कह रहे हैं कि जब जांचकर्ता और शिकायतकर्ता एक साथ केक काटते दिखाई दे रहे हैं तो क्या जांच होगी। जब यह पहले से ही मिले हैं इनसे न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं।

शिकायतकर्ता बच्चों के बारे में शंकराचार्य ने कहा कि सबसे बड़ी बात उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन, जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए जिन्हें मैं जानता नहीं हूं। एक सवाल के जवाब में कहा कि

अधिवक्ताओं का पैनल बना दिया है वह कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं। कहा कि अभी तक कोई जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करने नहीं आई है।

उघरहिं अंत न होइ निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू : शंकराचार्य ने रामचरित मानस के बालकांड की चौपाई उघरहिं अंत न होइ निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू का जिक्र करते हुए कहा कि यह बताती है कि कपट या ढोंग का अंत निश्चित है। पाखंडी का भेष (वेश) ज्यादा दिनों तक नहीं चलता और अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है, जैसे कालनेमि, रावण और राहु के कपट का अंत हुआ था। झूठ बोलने वालों की कलही भी ऐसे ही खुलेगी।

क्या देश के पीएम, राष्ट्रपति को नहीं पता उनके देश का शंकराचार्य दुराचारी हो गया : शंकराचार्य ने एक सवाल के जवाब में व्यंग्य करते हुए कहा कि क्या ये देश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उनके देश का शंकराचार्य दुराचारी हो गया। दूसरा प्रश्न यह कि शंकराचार्य जैसे निष्कलंक व्यक्ति पर कहानी बनाकर यह सब बातें कहना, क्या यह वह समझ नहीं रहे हैं।

आर्थक के बर्थडे पर हर्ष फायरिंग हुई थी..उसी पिस्टल से छात्रनेता के घर भी, पुलिस के रडार पर टॉप 24 दोस्त

गोरखपुर , एजेंसी। पुलिस का कहना है कि बर्थडे पार्टी के नाम पर समारोह में जमकर हंगामा हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक हाथों में पिस्टल लहराते हुए आर्थक के केक काटते ही कई राउंड फायरिंग कर रहे हैं। यह वीडियो अब पुलिस के लिए अहम साक्ष्य बन चुका है।

छात्रनेता उज्जवल यादव के घर पर हुई फायरिंग की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस की जांच से पता चला है कि जिस पिस्टल से उज्जवल के घर पर गोलियां चलाई गईं, उसी से एक दिन पहले आर्थक के जन्मदिन समारोह में खुलेआम हर्ष फायरिंग की गई थी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से पता चला है कि 20 फरवरी को हुई इस पार्टी में 24 से अधिक दोस्त शामिल हुए थे। पुलिस अब इस पार्टी में शामिल दोस्तों के बारे में जानकारियां जुटा रही है।

पुलिस का कहना है कि बर्थडे पार्टी के नाम पर समारोह में जमकर हंगामा हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक हाथों में पिस्टल लहराते हुए आर्थक के केक काटते ही कई राउंड फायरिंग कर रहे हैं। यह वीडियो अब पुलिस के लिए अहम साक्ष्य बन चुका है।

जांच में यह भी सामने आया है कि बर्थडे पार्टी में इस्तेमाल की गई पिस्टल ही छात्रनेता उज्जवल के घर पर दहशत फैलाने के लिए दोबारा निकाली गई। शनिवार देर रात हुई इस फायरिंग से मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। गोलियों की आवाज सुनकर लोग सहम गए और अपने-अपने घरों में दुबक गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम को छात्रनेता उज्जवल यादव के गेट के बाहर पिस्टल के आठ खाली खोखे मिले थे। इसे टीम ने अपने कब्जे में ले लिया था। उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों घटनाओं के वीडियो फुटेज कब्जे में लेकर तकनीकी जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। बर्थडे पार्टी में मौजूद युवकों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है।

हिरासत में लिए गए दो संदिग्ध युवकों से पूछताछ-एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आर्थक और उसके दो साथियों अनीश शुक्ला और विपिन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि आर्थक और उसके कई साथी पहले भी आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस उनके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने की तैयारी में जुटी है। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों के प्रदर्शन और फायरिंग जैसे गंभीर अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

न्यूरो आईडीकॉन 2026: बच्चों में बढ़ते ब्रेन इंफेक्शन पर चिंता, आगरा में जुटेंगे देशभर के न्यूरो एक्सपर्ट

आगरा, एजेंसी। 28 फरवरी और 1 मार्च को आगरा में आयोजित न्यूरो आईडीकॉन 2026 में देशभर के विशेषज्ञ मेनिनजाइटिस, इंसेफेलाइटिस और सीएनएस टीबी जैसे मस्तिष्क संक्रमण पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य बच्चों में मृत्यु और स्थायी विकलांगता को कम करने की रणनीति तैयार करना है। बच्चों में बढ़ते मस्तिष्क संक्रमण को लेकर 28 फरवरी और 1 मार्च को दो दिवसीय न्यूरो आईडीकॉन 2026 आयोजित किया जाएगा। फतेहाबाद रोड स्थित होटल में देश भर के बाल रोग विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट मेनिनजाइटिस, इंसेफेलाइटिस व सीएनएस टीबी सहित अन्य न्यूरो-इन्फेक्शन के आधुनिक उपचार और रोकथाम पर चर्चा करेंगे।

मंगलवार को कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया गया। मुख्य आयोजन अध्यक्ष डॉ. राकेश भाटिया और आयोजन सचिव डॉ.

अरुण जैन ने बताया कि भारत में हर वर्ष लाखों बच्चे इन गंभीर बीमारियों से प्रभावित होते हैं और कई मामलों में मृत्यु या स्थायी विकलांगता का खतरा रहता है। न्यूरो आईडीकॉन में बच्चों में न्यूरो-इन्फेक्शन से होने वाली मृत्यु और स्थायी विकलांगता को कम करने के लिए रणनीति तैयार करना है।

इस दौरान डॉ. आरएन द्विवेदी, डॉ. राजेश्वर दयाल, डॉ. आरएन शर्मा, डॉ. प्रदीप चावला, डॉ. संजय सक्सेना, डॉ. राजीव कृषक, डॉ. संजीव अग्रवाल, डॉ. स्वाति द्विवेदी सहित चिकित्सक मौजूद रहे। सम्मेलन में आईएपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. नीलम मोहन, अध्यक्ष निर्वाचित डॉ. सिंगारवेलू एम, राष्ट्रीय सचिव डॉ. रुचिरा माहेश्वरी गुप्ता सहित कई राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे।

न्यूरो-इन्फेक्शन पर वैज्ञानिक सत्र, विशेषज्ञों की पैनल चर्चा, केस-आधारित शिक्षण, शोध पत्र वाचन, कार्यशालाएं एवं आधुनिक उपचार पद्धतियों पर प्रस्तुति और टीकाकरण व रोकथाम रणनीतियों पर विशेष मंथन किया जाएगा।

शादी के दो दिन बाद ही विवाहिता की मौत, मां ने लगाया हत्या का आरोप, मातम में बदलीं खुशियां

गोरखपुर , एजेंसी। 22 फरवरी की शाम अचानक सीमा की तबीयत बिगड़ने की सूचना उसके मायके पक्ष को दी गई। ससुराल वालों ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सीमा के माता-पिता अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि वहां पहुंचने पर ससुराल पक्ष के लोग शव छोड़कर मौके से चले गए।

पीपीगंज थानाक्षेत्र में शादी की खुशियों के महज दो दिन बाद 21 वर्षीय नवविवाहिता सीमा की संदिग्ध हालात में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच कर रही है।

पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम सभा रत्नपुर निवासी कमल प्रभा देवी की बेटी सीमा का विवाह 20 फरवरी को पीपीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़नी निवासी मनोज के साथ हुई। परिजनों ने बताया कि विवाह में सामर्थ्य अनुसार दान-दहेज दिया गया। 21 फरवरी को सीमा की विदाई हुई और वह अपने ससुराल बढ़नी पहुंची।

बताया जाता है कि 22 फरवरी की शाम अचानक सीमा की तबीयत बिगड़ने की सूचना उसके मायके पक्ष को दी गई। ससुराल वालों ने उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सीमा के माता-पिता अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि वहां पहुंचने पर ससुराल पक्ष के लोग शव छोड़कर मौके से चले गए।

मृतका की मां कमल प्रभा देवी ने पीपीगंज पुलिस को सूचना देते हुए आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी के चलते उनकी बेटी की हत्या की गई। उन्होंने ससुराल पक्ष के खिलाफ तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चलेगा। फिलहाल तहरीर के आधार पर मामले की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा पाठ की कोशिश

लखनऊ, एजेंसी। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी भवन को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। जर्जर स्थिति के कारण भवन के दरवाजे बंद किए जाने के बाद परिसर में लगातार तीसरे दिन भी तनाव और हंगामे की स्थिति बनी रही। मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में सड़क पर नमाज पढ़े जाने के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं और अन्य छात्रों ने कई स्थानों पर हनुमान चालीसा पाठ करने की कोशिश की। इसके साथ ही लाल बारादरी के पास गंगाजल से शुद्धिकरण का प्रयास भी किया गया।

लाल बारादरी के निकट जतिन शुक्ला, शशि प्रकाश मिश्रा और विवेक मिश्रा की अगुवाई में दर्जनों छात्र माथे पर टीका लगाकर हनुमान चालीसा पाठ के लिए एकत्र हुए। जैसे ही छात्रों ने पाठ शुरू किया, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

इस दौरान मुख्य कुलानुशासक प्रो. राकेश द्विवेदी के नेतृत्व में प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने छात्रों

को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। छात्रों का कहना था कि परिसर में नमाज और इफ्तार कार्यक्रम होने पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि हनुमान चालीसा पर रोक लगाई जा रही है। टैगोर लाइब्रेरी के सामने स्थित पार्क में राष्ट्रीय शिक्षार्थी दल से जुड़े कुछ छात्रों ने गांधी प्रतिमा के पास हनुमान चालीसा पाठ कर नमाज और इफ्तार कार्यक्रम का विरोध जताया।

इधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने भी विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर प्रदर्शन करने की कोशिश की। पुलिस द्वारा रोके जाने पर उन्होंने कुल सचिव डॉ. भावना मिश्रा को ज्ञापन सौंपा।

छह पूर्व छात्रों के प्रवेश पर रोक, सात को नोटिस : लाल बारादरी परिसर में नमाज पढ़ने, इफ्तार आयोजन और भवन में तोड़फोड़ के आरोप में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सात छात्रों को नोटिस जारी किया है। वहीं छह पूर्व छात्रों के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस को पत्र भेजा गया है। विश्वविद्यालय प्रवक्ता प्रो. मुकुल श्रीवास्तव ने बताया कि परिसर में शांति और अनुशासन बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। नियमों के उल्लंघन के मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

मस्जिद नहीं है लाल बारादरी : प्रोफेसर घोष : राजधानी के वरिष्ठ इतिहासकार प्रोफेसर पीके घोष का कहना है कि लाल बारादरी का इतिहास में मस्जिद होने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस भवन की बनावट और आर्किटेक्चर मस्जिद के हिसाब से नहीं बना है। इसमें किबला और इसका मुख्य आर्च है ही नहीं। मस्जिद में होने वाला दालान भी नहीं है। खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर भी नहीं है। पुराने राजस्व रिकॉर्ड, नक्शे आदि में भी लाल बारादरी के मस्जिद होने का कोई जिक्र नहीं है।

क्या है मस्जिद में किबला : उन्होंने बताया कि मस्जिद में एक दीवार और मुख्य-आर्च मक्का की दिशा में होती है, जिसे किबला कहते हैं। मस्जिद में किबला सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित काबा की दिशा है, जिसकी ओर दुनिया भर के मुसलमान नमाज के दौरान अपना चेहरा रखते हैं।

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली के जनकपुरी में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मजदूर की मौत

नईदिल्ली, एजेंसी। पश्चिमी जिला के जनकपुरी इलाके में एक निर्माणाधीन मकान में काम

करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। यहां एक 32 वर्षीय प्रवासी मजदूर की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई है। मृतक की पहचान विजय एंक्लेव, डाबारी निवासी गुड्डू पटेल के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ।पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना जनकपुरी के सी2बी ब्लाक स्थित मकान नंबर 110सी की है। चश्मदीद और मृतक के साथी सुकत साह ने बताया कि वे दोनों ठेकेदार जगदीश के तहत यहां लेंटर डालने का काम कर रहे थे। सोमवार रात करीब 9 :00 बजे, जब गुड्डू पटेल चौथी मंजिल से लिफ्ट मशीन के जरिए नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी वह अचानक अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गया। उसके साथी उसे तुरंत माता चानन देवी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के साथी ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाए हैं कि मजदूरों ने काम शुरू करने से पहले ठेकेदार से हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट और दस्ताने जैसे सुरक्षा उपकरणों की मांग की थी। आरोप है कि ठेकेदार ने यह कहकर मांग ठुकरा दी कि कुछ नहीं होता, जल्दी काम खत्म करो। इसी सुरक्षा मानकों की इसी अनदेखी ने एक मजदूर की जान ले ली। पश्चिमी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जनकपुरी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 290/106 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने क्राइम टीम से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

बीसीडी चुनाव से गंदगी का बुरा हाल, सड़क पर लगे कूड़े के ढेर

नईदिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के चुनाव में मतदान के दौरान जहां लोग जाम से परेशान रहे वहीं मंगलवार को समाप्त हुए मतदान के बाद हाईकोर्ट के सामने गंदगी से बुरा हाल हो गया। अधिवक्ताओं व उनके समर्थकों के द्वारा मतदान के समय उड़ाए गए पर्चों से लेकर खाने की प्लेट सड़क पर कूड़े का ढेर बन गया। हाईकोर्ट के सामने की शेरशाह सूरी सड़क पर गंदगी से इस कदर स्थिति खराब हो गई है कि वह एनडीएमसी इलाका न होकर अनधिकृत कालोनी लग रही है। जहां जगह-जगह कूडे के ढेर लगे हुए हैं। वहीं सड़क भी प्रत्याशियों के समर्थन वाले पर्चों से सड़क पर इस कदर ढेर लग गया है कि सड़क को पहचान पाना मुश्किल है। कूड़ा इस कदर है कि एनडीएमसी के भी पसीने छूट गए हैं। नई दिल्ली इलाके में आम तौर पर ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती। बेहद वीवीआइपी इलाका होने के कारण यहां पर मशीनों से सफाई होती है। साथ ही गीले-सूखे कूड़े का अलग-अलग करने के कारण स्वच्छ सर्वेक्षण में भी एनडीएमसी का अच्छा स्थान रहता है। लेकिन बार काउंसिल के चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थकों ने सड़क पर खाने की प्लेट डाल दी हैं। बिखर रहा था। बचे हुए खाने की बदबू भी यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान कर रही थी। जबकि पर्चों के कारण भी ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के चुनाव में दिल्ली हाईकोर्ट ने गंदगी होने की वजह से काफी सख्त रुख अख्तियार किया था। जिसकी वजह से डीयू प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े। इतना ही नहीं चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के समर्थन में जो पर्चे उड़ाए जाते थे उसमें भी कमी आई है। हालांकि एनडीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि उसने दो गाड़ियों से कूड़ा उठवाया है बाकि का कार्य भी चल रहा है।

दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान उत्सव: बच्चों के लिए विज्ञान का अद्भुत मेला

नई दिल्ली। विज्ञान किताबों से बाहर निकलकर खेल, कहानियों, वर्चुअल अंतरिक्ष यात्राओं और प्रयोगों की रोमांचक दुनिया बन जाए तो बच्चों को कितना मजा आएगा न, कुछ ऐसा ही कुछ होने जा रहा है 28 फरवरी को आयोजित विज्ञान उत्सव में। तीन मूर्ति भवन के लॉन में नेहरू तारामंडल व प्रधानमंत्री संग्रहालय द्वारा आयोजित यह उत्सव, विज्ञान का ऐसा अद्भुत मेला होगा, जिसमें सीखना हंसी में मिलेगी तो ज्ञान रोमांचक अनुभव में तब्दील हो जाएगा। जिज्ञासा, रचनात्मकता और उत्सव की ऊर्जा से जीवंत हो उठेगा।

देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा खोजे गए 'रमन प्रभाव' की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश की वैज्ञानिक चेतना और नवाचार की भावना को समर्पित है। इस वर्ष विज्ञान उत्सव विज्ञान को कक्षा और पाठ्य पुस्तकों की सीमाओं से बाहर निकालकर जीवन के हर पहलू में जीवंत अनुभव के रूप में प्रस्तुत करेगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय व लाइब्रेरी के निदेशक अश्वनी लोहानी ने बताया कि यह निश्शुल्क है, लेकिन इसके लिए पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान केवल एक विषय नहीं है,

बल्कि यह सोचने, प्रश्न करने और भविष्य को आकार देने की प्रक्रिया है। विज्ञान उत्सव हमारा प्रयास है कि विज्ञान हर बच्चे और नागरिक के लिए सुलभ, रोचक और प्रेरणादायक बने।

सोसाइटी फार आल राउंड डेवलपमेंट की भविष्यवादी वर्ल्ड आन व्हील्स बस में बैठकर वर्चुअल रियलिटी (वीआर) के माध्यम से अंतरिक्ष, ग्रहों और ब्रह्मांड की रोमांचक यात्रा की जा सकेगी। यह बस केवल एक वाहन नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता डिजिटल कक्ष होगा। नेहरू तारामंडल की प्रोग्राम मैनेजर प्रेरणा चंद्रा ने बताया कि मेले में इसी तरह, वीआर हेडसेट्स के माध्यम से युवा प्रतिभागी खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान की गहराइयों को समझेंगे। इसी तरह, छात्रों को मेला परिसर में रोबोटिक्स प्रदर्शन, प्रयोग आधारित गतिविधियां, इंटरैक्टिव विज्ञान चुनौतियां, मोबाइल प्लैनेटेरियम जैसी गतविधियां कौतुहल जगाएंगी। जबकि, खगोल विज्ञान संवाद, रंगों का कोना, विज्ञान खेल, फोटो बूथ, डिस्कवरी जोन के साथ ही रात्रि में आकाश को टेलीस्कोप से निहारने जैसे न जाने कितने अन्य प्रयोग बच्चों को लुभाने वाले हैं। डीयू के किरोड़ी मल कॉलेज के एस्ट्रो क्लब व इंडियन नेटवर्क आफ फिजिक्स के छात्रों द्वारा इंटरैक्टिव विज्ञान खेल, रोचक प्रयोग और भौतिकी की चुनौतीपूर्ण गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जहां छात्र न सिर्फ विज्ञान देखेंगे नहीं बल्कि स्वयं उसका अनुभव करेंगे।

दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर फायरिंग

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में मंगलवार देर रात एक कार पर फायरिंग की घटना सामने आई। कार में पांच लोग सवार थे, जिनमें से एक घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, कार में मौजूद एक व्यक्ति वकील दीपक खत्री हैं, जो खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम का हिस्सा बता रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें बिश्नोई का वकील बताया गया है। पुलिस ने बताया कि दो या तीन हमलावरों ने फायरिंग की। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। वहीं घायल व्यक्ति की हालत स्थिर है और जांच जारी है। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार में सवार लोगों में से एक शख्स ने बताया कि रात करीब 10 :15 बजे वे एक मंदिर से निकले थे। हम कार में बैठे ही थे, तभी हम पर तीन गोलियां चलाई गईं। जब पीछे का शीशा टूटा, तब हमें पता चला कि हम पर गोलियां चलाई जा रही हैं। मेरे एक दोस्त संदीप की पीठ में गोली लगी है। हम तेजी से गाड़ी भगाकर वहां से निकल गए। पीसीआर समय पर पहुंच गई और हमारे दोस्त को अस्पताल ले गई। गाड़ी सवार अन्य लोगों की हालत स्थिर है। पुलिस घटना का सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ितों से पुलिस बयान लेकर जांच शुरू कर दी है।

दशकों बाद पुरानी दिल्ली को लटकते तारों से मिलेगी मुक्ति

भूमिगत परियोजना का होगा शुभारंभ

नई दिल्ली, एजेंसी। दशकों की मांग और प्रयासों के बाद आखिरकार पुरानी दिल्ली में लटकते तारों को भूमिगत करने की परियोजना को गति मिलने जा रही है।

शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी) की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा बृहस्पतिवार को पुरानी दिल्ली की सड़कों, कूचों व कटरों में तारों को भूमिगत करने की परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए कुछ दिन पूर्व राज्य सरकार ने 159.47 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।

सूत्रों के अनुसार इस मौके पर ऊर्जा मंत्री आशीष सूद, सांसद प्रवीन खंडेलवाल और पार्षद सुमन गुप्ता समेत अन्य मौजूद रहेंगे। विशेष बात कि द्वितीय चरण में कुल 26 सड़कों, कटरों व कूचों में लटकते तारों को भूमिगत किया जाएगा। बिजली वितरण कंपनियों को तारों को भूमिगत करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। चरणबद्ध तरीके से काम होगा।

चांदनी चौक का सांसद बनने के बाद प्रवीन खंडेलवाल ने इस समस्या के समाधान को लेकर व्यापारियों और अधिकारियों के साथ समग्र चर्चा कर रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंपी थी। मौजूदा समय में चांदनी चौक, नई सड़क, किनारी बाजार, दरीबा, कूचा महाजनी, भागीरथ पैलेस, चावड़ी बाजार, लाल कुंआ, मटिया महल समेत कमोबेश पुरानी दिल्ली की हर सड़क और गलियों में लटकते बिजली के तार मिल जाएंगे। कहीं-कहीं यह खतरनाक स्थिति में काफी नीचे तक चले आए हैं।

तारों के इस मकड़जाल से अक्सर अगलगी की घटनाएं हुईं। इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार चिंता जताई तथा आदेश दिए थे। सरकारी सूत्रों के अनुसार, हवेली धर्मपुरा, कौड़िया पुल, मस्जिद खजूर समेत सभी मार्गों पर प्राथमिकता के स्तर पर तारों को भूमिगत किया जाएगा।

उसमें बिजली के तारों के साथ ही इंटरनेट, केबल समेत अन्य तारों के लिए भी अलग से डक्ट डाले जाएंगे। वैसे, इसके पूर्व एसआरडीसी की प्रथम चरण की परियोजना के तहत चांदनी चौक मुख्य मार्ग पर तारों को भूमिगत किया गया है, लेकिन गलियों और अन्य इलाकों का मामला अटका रहा।

एसआरडीसी परियोजना के तहत चांदनी चौक में तार भूमिगत करने का काम शुरू, लेकिन पूरा नहीं हुआ।

एसआरडीसी परियोजना के तहत चांदनी चौक मुख्य मार्ग पर डक्ट डालने का काम शुरू हुआ, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक को टाइम बम कहा, तारों के जाल पर चिंता जताई। लाल जैन मंदिर से फतेहपुरी चौक तक 1.3 किमी मुख्य मार्ग पर तारों को भूमिगत करने की परियोजना शुरू व वर्ष 2021 में हुआ पूरा।

निर्माण के लिए 14 वृक्षों के प्रत्यारोपण की अनुमति दी

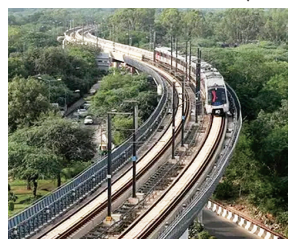

आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पर डीएमआरसी को 40 वृक्षों के प्रत्यारोपण की मिली अनुमति

नईदिल्ली, एजेंसी। वन विभाग ने दिल्ली जन तीव्र पारगमन प्रणाली (एमआरटीएस) परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के निर्माण कार्यों के लिए 40 वृक्षों के प्रत्यारोपण की अनुमति देते हुए दो अलग-अलग अनुमतियां जारी की हैं। 13 जनवरी को जारी पहले आदेश में, विभाग ने आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन (लाइन-8) पर क्रासओवर के निर्माण के लिए 14 वृक्षों के प्रत्यारोपण की अनुमति दी। दस्तावेज़ में कहा गया है कि ये वृक्ष प्रस्तावित क्रासओवर के निर्माण क्षेत्र में आते हैं और अनुमति देने से पहले स्थल निरीक्षण के दौरान इनकी

जांच की गई थी। आदेश में डीएमआरसी को 140 पौधों का क्षतिपूर्ति रोपण करने का भी निर्देश दिया गया है, जो प्रत्यारोपण के लिए स्वीकृत वृक्षों की संख्या से 10 गुना अधिक है। आधिकारिक दस्तावेज़ में दर्ज है कि डीएमआरसी ने प्रत्यारोपण के लिए 7.98 लाख रुपये की सुरक्षा राशि जमा की है। चार फरवरी को जारी दूसरे आदेश में, विभाग ने आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पर बॉक्स पुशिंग शाफ्ट के निर्माण के लिए 26 वृक्षों के प्रत्यारोपण की अनुमति दी। लेकिन निरीक्षण के बाद यह संख्या घटाकर 26 कर दी गई, जिनमें से सात पेड़ों को बचा लिया गया। इस आदेश के अनुसार, डीएमआरसी को नरेला डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में 260 पौधों का क्षतिपूर्ति रोपण करने और सात वर्षों तक उनकी देखभाल करने का निर्देश दिया गया है।

स्थानांतरण पर एनजीटी ने डीपीसीसी पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना

नईदिल्ली, एजेंसी। वन एवं वन्यजीव विभाग को क्षतिपूर्ति शुल्क स्थानांतरित करने में बहुत ज्यादा देरी के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डीपीसीसी के बेबुनियाद बहाने बनाकर एनजीटी के आदेशों का पालन नहीं किया और क्षतिपूर्ति राशि स्थानांतरित करने में देरी का कारण स्वीकार्य नहीं हैं। एनजीटी ने रिकार्ड पर लिया कि क्षतिपूर्ति शुल्क के स्थानांतरण में देरी उसके कार्यालय की शिफ्टिंग के कारण हुई थी। एनजीटी ने कहा कि शुल्क के स्थानांतरण में एक साल से अधिक की देरी को लेकर बताया गया कारण पूरी तरह से गलत है। एनजीटी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश का पालन करना एक अपराध है और डीपीसीसी के चेयरमैन और सदस्य सचिव पर भी ऐसे उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। एनजीटी ने कहा कि हालांकि, ट्रिब्यूनल मुकदमा चलाने का निर्देश देना उचित नहीं समझता। यूनिट से पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर इकट्ठा किए गए आठ लाख रुपये वन एवं वन्यजीव विभाग को जारी करने का निर्देश दिया था। साथ ही विभाग को निर्देश दिया गया था कि उक्त धनराशि का उपयोग गांव में पेड़ लगाने के कामों के लिए किया जाएगा।

जरूरी खनिजों पर चीन की पकड़ से रक्षा उद्योग को खतरा', अमेरिकी सांसदों ने दी चेतावनी

'चीन पर अमेरिका की निर्भरता सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी'

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिजों और आधुनिक तकनीकी सप्लाई चेन्स को लेकर चिंता बढ़ रही है। अमेरिकी सांसदों ने चेतावनी दी है कि महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन का दबदबा संकट के समय में अमेरिकी रक्षा उद्योग को कमजोर कर सकता है। वहीं, पेंटागन ने घरेलू सप्लाई चेन के पुनर्निर्माण के लिए किए गए विवादित इक्विटी निवेश और मूल्य गारंटी का बचाव किया है।

सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने सप्लाई चेन के पुनर्निर्माण पर कांग्रेस की सुनवाई में कहा, 'यह कोई बढ़ा-चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन के पर अमेरिका की निर्भरता हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरियों में से एक है।' उन्होंने चेतावनी दी कि दुर्लभ धातुओं (रेयर अर्थ) के निर्यात में

कटौती की धमकियों से अमेरिकी रक्षा उत्पादन घुटनों पर आ जाता और अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होता। पेंटागन औद्योगिक नीति प्रमुख माइकल कैडेनाजी ने सीनेटरों को बताया कि यह जोखिम तत्काल है। उन्होंने कहा, 'यह कोई सैद्धांतिक जोखिम नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट और मौजूदा खतरा है।' उन्होंने चेतावनी दी कि बीजिंग इन सप्लाई चेन को हथियार बना सकता है, जिससे हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस में रुकावट आने और संकट में मिलिट्री की तैयारी से समझौता करने का खतरा है। कैडेनाजी ने बताया कि विभाग ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत और इंडस्ट्रियल बेस फंड के जरिए खनिज क्षेत्र में 97 करोड़ डॉलर का निवेश किया गया और अमेरिका एक व्यापक रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें उत्पादन को वापस लाना, सहयोगियों के साथ काम करना, रिसर्च और रीसाइक्लिंग में निवेश व राष्ट्रीय रक्षा भंडार का आधुनिकीकरण करना शामिल है। उन्होंने दुर्लभ धातुओं के उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए 'एमपी मैटेरियल्स समझौते' का जिक्र किया।

बलूच संगठनों का अफगानिस्तान को समर्थन का ऐलान

बलूच, एजेंसी। बलूच संगठन ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए गए कथित हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। संगठन ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया।अफगानिस्तान के के अनुसार पाकिस्तान ने नंगरहार और पक्तिका प्रांतों के रिहायशी इलाकों में हवाई हमले किए। दावा किया गया कि एक मदरसे को निशाना बनाया गया कई रिहायशी घर तबाह हुए महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों नागरिक मारे गए या घायल हुए हालांकि पाकिस्तान की ओर से इस पर आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ब्नहरूने कहा द्वद्ध पिछले 79 वर्षों से क्षेत्रीय अस्थिरता की मुख्य वजह पाकिस्तान की नीतियां हैं। पाकिस्तान पर विस्तारवादी और आंतरिक दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया। बलूचिस्तान के कब्जे और वहां राजनीतिक दमन का जिक्र किया। संगठन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं से

ध्यान हटाने के लिए पड़ोसी देशों पर दबाव बनाता है। बीएनएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अफगानिस्तान की संप्रभुता और आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। उसने क्षेत्रीय देशों से संयुक्त मोर्चा बनाने की अपील की ताकि कथित सैन्य आक्रामकता का मुकाबला किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह के हमले जारी रहे तो पाकिस्तान-अफगानिस्तान संबंध और बिगड़ सकते हैं। सीमा पर सैन्य तनाव बढ़ सकता है और क्षेत्र में अस्थिरता और उग्रवाद को बढ़ावा मिल सकता है।

खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब प्रांत तक आतंक का साया

● पुलिस वैन पर हमले से सात की मौत

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाके में पुलिस पर हुए दोहरे हमले ने सुरक्षा हालात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में संदिग्ध आतंकियों ने पुलिस वाहनों को निशाना बनाकर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में कम से कम छह पुलिसकर्मियों और एक आम नागरिक की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पहला हमला कोहाट में एक पुलिस वाहन पर किया गया, जिसमें एक अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही मिनट बाद जब अतिरिक्त पुलिस बल वहां पहुंचा तो हमलावरों ने दोबारा हमला कर दिया। इस दूसरी घात में पांच और पुलिसकर्मी तथा एक नागरिक मारे गए। हमलावर घटना के बाद फरार हो गए और इलाके में सर्च अभियान शुरू किया गया है।

इसी दिन पंजाब प्रांत के बुकर जिले में एक पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस विस्फोट में दो पुलिस अधिकारियों की मौत हुई और चार अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि हमले की जांच जारी है और अभी किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा एजेंसियां संभावित आतंकी नेटवर्क की तलाश में जुटी हैं। अर्धसैनिक चौकी पर विस्फोटकों से लदे ड्रोन से हमला किया गया था। इस हमले में कई अधिकारी घायल हुए। बाद में घायलों को ले जा रही एंबुलेंस पर भी घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें तीन अधिकारियों की मौत हो गई और उनके शव जला दिए गए। एक एंबुलेंस चालक खुद झुलसने के बावजूद घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सफल रहा। इन घटनाओं ने सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया है। हालिया हमलों की जिम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली है, लेकिन शक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पर जताया जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान की जमीन से काम करते हैं।

संपादकीय | भारत ब्राजील समझौते के क्या हैं मायने

मौजूदा दौर में दुनिया भर में भू-राजनीति के स्वरूप में जिस तेजी से उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं, उसमें सभी देशों के सामने अपने भविष्य और विकास की राह सुरक्षित करने की चुनौती दिख रही है। खासतौर पर जिन कारकों पर आने वाले वर्षों में विकास की दिशा निर्भर करेगी, उसके मद्देनजर अलग-अलग देशों के बीच साझेदारी के नए अध्याय तैयार हो रहे हैं, विकल्प की राह खोजी जा रही है। भारत और ब्राजील के बीच हुए समझौते को इसी की एक कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से उन बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसमें सहयोग के क्षेत्र में विकल्प के नए रास्ते तैयार हों। आज दुनिया भर में यह चिंता सतह पर देखी जा रही है कि आने वाले वर्षों में विकास का आधार बनने वाले अहम कारकों को लेकर कैसे एक नई आपूर्ति श्रृंखला बनाई जाए।

भारत-ब्राजील के बीच हुआ समझौता इसी संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि इसके जरिए दोनों को अन्य मजबूत देशों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि इस समझौते में अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बीस अरब डालर से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में काफी महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समझौते में सबसे अहम सहमति दुर्लभ खनिजों और भू-धातुओं को लेकर बनी है, जो आने वाले वर्षों में समूची दुनिया में विकास के सबसे अहम कारक बनने वाले हैं।

इससे तकनीक के क्षेत्र में आदान-प्रदान, नई संभावनाओं की खोज, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह जगजाहिर तथ्य है कि आज लीथियम और कोबाल्ट जैसे अन्य दुर्लभ

खनिज तथा भू-धातु विकास के संचालक तत्त्व बन रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जिस तरह इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा क्षेत्र, आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण और रोबोटिक्स उत्पादन के क्षेत्र में सभी देश अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं और इस संबंध में ज्यादा बेहतर अवसरों की तलाश में हैं। ऐसे में दुर्लभ खनिजों की मांग में काफी तेजी आने की उम्मीद है। फिलहाल वैश्विक स्तर पर दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण के सबसे बड़े हिस्से पर चीन का नियंत्रण है। भारत-ब्राजील के बीच हुए समझौते का एक मुख्य उद्देश्य आधुनिक उद्योग और तकनीक के लिए आवश्यक सामग्री की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना है और साथ ही इस क्षेत्र के प्रमुख आपूर्तिकर्ता और खासतौर पर चीन पर निर्भरता को कम करना है। भारत के लिए यह समझौता इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि ब्राजील को चीन के बाद दुर्लभ खनिजों से समृद्ध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। ब्राजील के साथ नए करार के बाद भारत को इन खनिजों को सीधे हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को लेकर एक सहमति बनी है। इसका असर छोटे कारोबारियों पर भी पड़ेगा और उन्हें नई तकनीकों के साथ-साथ ब्राजील के बाजार और उसकी नीतियों के अनुकूल अपना रुख तय करने का मौका मिलेगा। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल क्षेत्र में विकास के अन्य अहम बिंदुओं पर भी सहयोग के नए आयाम खुले हैं। दोनों देशों के बीच साझेदारी ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका व्यापार समझौते में भारत के सामने अपने फायदे में शर्तें सामने रख रहा है। हालांकि यह ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुध्रुवीय विश्व में अगर कोई विकसित देश अपने हित में विकासशील देशों पर दबाव को औजार बनाता है, तो आज एक बेहतर कूटनीति विकल्प की राह तैयार कर सकती है।

राष्ट्रीय खिलाड़ी की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने उठाए गंभीर सवाल

हरियाणा के रोहतक जिले में पिछले साल बास्केटबाल का खंभा गिरने से एक युवा राष्ट्रीय खिलाड़ी की मौत ने शासकीय लापरवाही और भ्रष्टाचार की कई परतें भी खोल दी थीं। तब इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने इसकी हर पहलू से जांच करने और जरूरत के मुताबिक सुधार के कदम उठाने की बात कही थी। घटना के बाद एक जांच समिति भी गठित की गई थी, मगर हालत यह है कि अब तक उस समिति की विस्तृत रपट नहीं पेश की गई।यही वजह है कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने खिलाड़ी की मौत पर चिंता जताते हुए इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन बताया है। गौरतलब है कि रोहतक के उपायुक्त की ओर से जो

रपट भेजी गई, उसमें घटना के वास्तविक कारणों और सुरक्षा मानकों का ठोस ब्योरा तक नहीं है। इसमें केवल बास्केटबाल स्टेडियम बनाने के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने का जिक्र है। आयोग ने इसे संज्ञान में लिया है और अब पूरे मामले पर सरकार से रपट मांगी है। यह दुखद है कि खेलों के लिए पर्याप्त राशि खर्च किए जाने पर भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिलता और खेल सुविधाओं में गुणवत्ता नहीं दिखती। बास्केटबाल मैदान में अगर खंभे में जंग लगी थी और वह कमजोर होने के कारण गिरने की स्थिति में था, तो वहां किसी खिलाड़ी को अभ्यास करने या खेलने से रोकना और खंभा तुरंत बदलना किसकी जिम्मेदारी थी? अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बार-बार की शिकायत के बावजूद उस खंभे की न मरम्मत की गई और न उसे हटाया गया। सच यह है कि खेल के मैदान में नियमित रखरखाव होता, तो अभ्यास के दौरान बास्केटबाल खिलाड़ी की जान नहीं जाती। आयोग ने साफ तौर कहा है कि यह संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही और उनके कर्तव्यों में चूक है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा और चिंता का कारण बनने के बावजूद इस मसले पर राज्य सरकार की उदासीनता और अनदेखी एक अघोषित नीति है! वरना जांच रपट में देरी न करना और इस मसले पर जरूरी कदम उठाना उसकी नजर में प्राथमिक दायित्व होता।

आज का कार्टून

तकनीक के दुरुपयोग का फैलता दायरा...

आज भारत एक डिजिटल समाज बनने की ओर अग्रसर है, मगर अब भी बड़ी संख्या में लोग डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं। अगर साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो निकट भविष्य में इसके भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। यह विफलता हमारे समाज को नकदी-आधारित प्रणालियों की ओर फिर से रुख करने के लिए मजबूर कर सकती है। मगर हम नवाचार, संस्थागत सहयोग और नैतिक प्रारूप के सही संयोजन के साथ सुरक्षात्मक उपाय तलाशेंगे, तो न केवल देश में इस खतरे को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर भी मिसाल कायम कर सकते हैं। इसलिए तेजी से बदलते डिजिटल दौर में खुद को आगे रखने के लिए सरकार, प्रौद्योगिकी क्षेत्र और समाज के बीच एक समन्वित एवं सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही सतर्कता, डिजिटल अनुशासन और विशेषज्ञों की ओर से सुझाए गए व्यावहारिक उपायों के जरिए इस खतरे को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

रवि शंकर

हाल के वर्षों में भारत ने विभिन्न सेवाओं के डिजिटलीकरण में खासी प्रगति की है। देश में नब्बे करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हो गए हैं, जिससे डिजिटल माध्यम से पैसे के लेन-देन और अन्य कार्यों को पूरा करने का चलन भी बढ़ा है। इसी की बदौलत भारत ने दुनिया के सबसे बड़े 'रियल-टाइम' भुगतान बाजार के रूप में खुद को परिवर्तित किया है। वर्ष 2017 और 2023 के बीच 'रिटेल डिजिटल भुगतान' में 50.8 फीसद की तेज वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014 में यह देश की जीडीपी का 4.5 फीसद हिस्सा था और 2026 के अंत तक इसके बीस फीसद तक पहुंचने का अनुमान है। मगर डिजिटल तकनीक के तेजी से हो रहे प्रसार के साथ कई साइबर संबंधी समस्याएं भी सामने आई हैं।

आज अक्सर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां लोग साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। भले ही डिजिटल समावेशन का सपना अब देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंच चुका है, लेकिन इस उपलब्धि के साथ कई तरह की चुनौतियां भी पैदा हो गई हैं। तकनीक का दुरुपयोग सुरक्षा में सेंध लगा रहा है और इस तरह के अपराध पर लगाम लगाना सुरक्षा एजंसियों के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 के बाद से देश में साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं में करीब चार सौ फीसद की वृद्धि हुई है। अब ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्र डिजिटल ठगी के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। कुछ शहरों में साइबर सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण वहां इस तरह के अपराध तेजी से बढ़े हैं।

ग्रामीण इलाकों में भी साइबर अपराध का बढ़ना कोई संयोग नहीं, बल्कि यह सामाजिक और तकनीकी बदलाव का नतीजा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने डिजिटल पहुंच तो बढ़ा दी है, लेकिन लोगों में डिजिटल समझ नहीं बढ़ी है।

सट्टेबाजी और आनलाइन खेल ऐप, जो मनोरंजन के रूप में पेश किए जाते हैं, वे साइबर ठगी के आसान जरिया बन गए हैं। यही वजह है कि पिछले छह साल में आनलाइन धोखाधड़ी के कारण भारतीयों को 52 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। यह जानकारी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ताजा आंकड़ों से सामने आई है।

समन्वय केंद्र की रपट में कहा गया है कि वर्ष 2025 में देश के नागरिकों ने करीब 19,813 करोड़ रुपए साइबर धोखाधड़ी में गंवाए हैं। इस दौरान 21 लाख से ज्यादा शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज हुईं। इससे पहले वर्ष 2024 में 22,849 करोड़ रुपए का नुकसान और लगभग 19 लाख शिकायतें सामने आईं।

आज जब ज्यादातर चीजें मोबाइल और इंटरनेट पर सुलभ हैं, वहीं साइबर अपराधी भी हर उस चूक का इंतजार करते हैं, जो आम लोग अनजाने में कर बैठते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि लोग खुद को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित और सतर्क बनाएं। समस्या इसलिए भी जटिल होती जा रही है कि साइबर अपराधी ठगी के लिए नए-नए तरीके अपनाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी देश भर में बढ़ रहे डिजिटल अपराध से निपटने के लिए सरकार को

उचित एवं प्रभावी कदम उठाने को कहा।

शीर्ष अदालत के मुताबिक, डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों और संबंधित अधिकारियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर ठगी के मामलों में पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक राहत मुहैया कराने की मांग भी उठ रही है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है।

माना जा रहा है कि आरबीआइ एक नया नियम बना सकता है, जिसके तहत साइबर ठगी के छोटे मामलों में पीड़ित को पच्चीस हजार रुपए की आर्थिक मदद मिल सकती है। मगर यह तभी संभव होगा, जब पीड़ित व्यक्ति समय पर बैंक को इस तरह की धोखाधड़ी की जानकारी देगा।

साइबर अपराध बढ़ने से आम लोगों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालात ये हैं कि साइबर अपराध अब केवल तकनीकी चूक का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह व्यक्तिगत गोपनीयता और समग्र डिजिटल व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। आज साइबर ठगी केवल ई-मेल या फोन काल तक सीमित नहीं रह गई है।

'एआइ वायस क्लोनिंग', 'डीपफेक वीडियो', नकली ऐप और सोशल मीडिया पर बनाए गए फर्जी प्रोफाइल के जरिए अपराधी आम लोगों पर मानसिक दबाव बनाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। कई मामलों में जालसाज खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस अफसर, आयकर अधिकारी या किसी करीबी रिश्तेदार के रूप में पेश कर तत्काल भुगतान की मांग करते हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा अब महज पैसों के नुकसान से बचाने का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बन चुका है।

एक रपट के मुताबिक, भारत में डिजिटल तरीके से वित्तीय लेन-देन अब बड़े पैमाने पर होने लगा है। इसलिए साइबर सुरक्षा अब सिर्फ तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि डिजिटल व्यवस्था में नागरिकों के भरोसे को कायम रखने के लिए भी जरूरी है। सरकार ने साइबर ठगी को रोकने के लिए कानून जरूर बनाए हैं, लेकिन आज भी इनका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन, तथ्य जांच और वास्तविक समय में निगरानी जैसी प्रणालियां बहुत धीमी गति से काम करती हैं।

जाहिर है, किसी एक एजंसी पर जिम्मेदारी डालने से साइबर अपराध पर अंकुश लगाना संभव नहीं है। इसके लिए केंद्र-राज्य सरकारें, बैंकिंग-वित्तीय संस्थान, टेक कंपनियां और आम नागरिक, सभी को एकजुट होकर एक रणनीति के साथ काम करना होगा। इसमें दोराय नहीं कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ डिजिटल धोखाधड़ी का दायरा भी बढ़ रहा है।

ऐसे में संदिग्धों का पंजीकरण इस तरह के मामलों से निपटने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, लेकिन यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना और नागरिकों में सतर्कता एवं जागरूकता को प्रोत्साहित करना भी उतना ही अहम है। नीति निर्माताओं को नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा को केंद्र में रखना होगा।

आज भारत एक डिजिटल समाज बनने की ओर अग्रसर है, मगर अब भी बड़ी संख्या में लोग डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं। अगर साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो निकट भविष्य में इसके भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं। यह विफलता हमारे समाज को नकदी-आधारित प्रणालियों की ओर फिर से रुख करने के लिए मजबूर कर सकती है।

मगर हम नवाचार, संस्थागत सहयोग और नैतिक प्रारूप के सही संयोजन के साथ सुरक्षात्मक उपाय तलाशेंगे, तो न केवल देश में इस खतरे को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर भी मिसाल कायम कर सकते हैं। इसलिए तेजी से बदलते डिजिटल दौर में खुद को आगे रखने के लिए सरकार, प्रौद्योगिकी क्षेत्र और समाज के बीच एक समन्वित एवं सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही सतर्कता, डिजिटल अनुशासन और विशेषज्ञों की ओर से सुझाए गए व्यावहारिक उपायों के जरिए इस खतरे को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

नये भारत की नई प्रहार नीति...

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देश की पहली समग्र आतंक विरोधी नीति जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंक के खिलाफ संघर्ष एक संगठित और आक्रामक ढांचे के तहत लड़ा जाएगा। इस नीति का नाम रखा गया है प्रहार। नाम ही संकेत दे रहा है कि यह नीति रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रतिघात और प्रतिकार की सोच पर आधारित है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दस्तावेज में साफ कहा गया है कि भारत को सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद के साथ-साथ साइबर हमलों, ड्रोन के दुरुपयोग और उभरती तकनीकों के जरिये हो रहे हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि अपराधी हैकर और कुछ राष्ट्र लगातार साइबर हमलों के जरिये भारत को निशाना बना रहे हैं। यह खतरा अब केवल बंदूक और बारूद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि की-बोर्ड, कोड और क्रिप्टो वॉलेट तक फैल चुका है।

नीरज कुमार दुबे

नीति में यह रेखांकित किया गया है कि भारत जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर आतंकी खतरों से जूझ रहा है। बिजली, रेल, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा क्षमता को मजबूत किया गया है ताकि राज्य और गैर राज्य तत्वों की साजिशों को विफल किया जा सके। यह स्पष्ट संकेत है कि अब आतंक के खिलाफ केवल घटनाओं के बाद कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि रणनीतिक तैयारी पहले से की जाएगी।

दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि भारत आतंकवाद को किसी विशेष धर्म, जाति या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ता। लेकिन यह भी उतनी ही स्पष्टता से दर्ज किया गया है कि सीमा पार से प्रायोजित जिहादी आतंकी संगठन और उनके सहयोगी भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचते रहे हैं। अल कायदा और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों का नाम लेते हुए नीति में कहा गया है कि ये संगठन स्लीपर सेल के जरिये भारत में हिंसा भड़काने की कोशिश करते रहे हैं। विशेष चिंता का विषय ड्रोन और रोबोटिक तकनीक का दुरुपयोग है, खासकर पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में। हथियार और मादक पदार्थ गिराने से लेकर आतंकी हमलों की साजिश तक, तकनीक का

इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया, एन्क्रिप्शन टूल, डॉर्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट के जरिये फंडिंग और प्रचार का नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। नीति इस डिजिटल युद्ध को पहचानते हुए सीबीआरएनईडी यानी रासायनिक, जैविक, विकिरण, परमाणु, विस्फोटक और डिजिटल सामग्री तक आतंकी पहुंच को रोकने की चुनौती पर जोर देती है।

गृह मंत्रालय ने जांच की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर कानूनी विशेषज्ञों को जोड़ने की सिफारिश की है ताकि एफआईआर से लेकर अभियोजन तक केस मजबूत बन सके। यह कदम आतंक के खिलाफ अदालतों में निर्णायक सजा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

कट्टरपंथ के मुद्दे पर भी नीति स्पष्ट है। अक्सर देखने में आता है कि आतंकी संगठन भारतीय युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में चरणबद्ध पुलिस प्रतिक्रिया, कानूनी कार्रवाई और पुनर्वास कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है। समुदाय और धार्मिक नेताओं की भूमिका को भी रेखांकित करते हुए कहा गया है कि जागरूकता और संवाद के जरिये युवाओं को भटकने से रोका जाएगा। जेलों में भी डि रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम चलाने की बात कही गई है।

यह नीति केवल घरेलू ढांचा नहीं है। इसमें अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग की भी आवश्यकता पर बल दिया गया है, क्योंकि आतंक का नेटवर्क सीमाओं से परे फैला हुआ है। विदेशी संगठन स्थानीय ढांचे और भूगोल का उपयोग कर हमले की साजिश रचते हैं। ऐसे में समन्वित वैश्विक कार्रवाई जरूरी है।

देखा जाये तो प्रहार नीति वस्तुतः उस बदले हुए भारत को दर्शाती है जो अब आतंकवाद को नियति मानकर सहने वाला राष्ट्र नहीं रहा। पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पार आतंकवाद का जवाब केवल कूटनीतिक नोटिस से नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई से दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब यह नीति उस सोच को संस्थागत रूप दे रही है।

भारत की प्रहार नीति का सामरिक महत्व अत्यंत गहरा है। यह स्पष्ट संदेश देती है कि भारत बहु आयामी युद्ध को समझता है। आतंक अब केवल सीमा पर घुसपैठ नहीं, बल्कि साइबर स्पेस, वित्तीय नेटवर्क और वैचारिक प्रचार के जरिये भी फैलाया जाता है। प्रहार इन सभी मोर्चों पर एकीकृत प्रतिक्रिया का ढांचा प्रस्तुत करता है। साथ ही यह नीति रक्षात्मक मानसिकता से बाहर निकलकर सक्रिय प्रतिरोध और पूर्व तैयारी की रणनीति अपनाती है। इसके अलावा, यह कानून, तकनीक और समाज तीनों को एक साथ जोड़ती है।

सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीति ने स्पष्ट कर दिया है कि अब धैर्य की भी सीमा है। कश्मीर में आतंकी ढांचे को तोड़ने, फंडिंग पर नकेल कसने और अलगाववादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के कदमों ने जमीन पर असर दिखाया है। प्रहार उसी क्रम का अगला चरण है जहां आतंक के हर स्वरूप को चिन्हित कर व्यवस्थित ढंग से कुचला जाएगा।

जो लोग आतंक के खिलाफ कठोर नीति को लेकर संशय जताते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा भावनात्मक उदारता से नहीं बल्कि कठोर निर्णयों से सुरक्षित होती है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी धर्म को आतंक से नहीं जोड़ता, लेकिन आतंक के नाम पर देश को अस्थिर करने की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देगा।

बहरहाल, प्रहार नीति एक संदेश है कि नया भारत हमले का इंतजार नहीं करता, बल्कि खतरे की पहचान कर पहले ही प्रहार करता है। यही रणनीतिक परिपक्वता किसी भी उभरती शक्ति की पहचान होती है। आतंक के खिलाफ यह संगठित, आक्रामक और समन्वित दृष्टिकोण आने वाले समय में भारत की सुरक्षा संरचना को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

बॉक्सिंग में मेवेदर और पैकियाओ के बीच ऐतिहासिक री-मैच सितंबर में

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फाइट के दोनों दिग्गज बॉक्सर एक बार फिर होंगे आमने-सामने

लास वेगास (एजेंसी)। मुक्केबाजी की दुनिया के दो सबसे बड़े दिग्गज फ्लॉयड मेवेदर जूनियर और मैनी पैकियाओ एक बार फिर प्रोफेशनल रिंग में आमने-सामने होंगे। इस ऐतिहासिक री-मैच की घोषणा कर दी गई है, जो 19 सितंबर को लास वेगास के अत्याधुनिक 'द स्फीयर' में होगा। दोनों खिलाड़ी 11 साल बाद एक बार फिर आमने-सामने होंगे। इससे पहले 2 मई 2015 को हुई उनकी

पहली भिड़ंत ने कमाई और व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। उस फाइट से 410 मिलियन डॉलर (करीब 2680 करोड़ रुपए) का रेवेन्यू जनरेट हुआ था जबकि टिकट विंडो से 72.2 मिलियन डॉलर (करीब 470 करोड़) की कमाई हुई थी। वह मुकाबला मेवेदर ने अपने नाम किया था।

मेवेदर का 50-0 का परफेक्ट रिकॉर्ड जबकि पैकियाओ ने पिछले साल की थी वापसी- अमेरिका के मेवेदर ने हाल ही में रिंग में वापसी की पुष्टि की। 49 वर्षीय मेवेदर 2017 में कोनोर मैक्ग्रेगोर को हराने के बाद 50-0 के परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ रिटायर हुए थे। वहीं, फिलीपींस के 47 वर्षीय पैकियाओ ने भी 2025 में मारियो बैरियोस के खिलाफ ड्रॉ खेलकर रिंग में वापसी की है। उन्होंने करियर में 73 फाइट में से 62 जीती हैं।

रिंकू के पिता नोएडा के अस्पताल में भर्ती

- **क्रिकेटर टीम इंडिया को छोड़कर घर लौटे, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना मुश्किल**

अलीगढ़ (एजेंसी)। क्रिकेटर रिंकू सिंह टीम इंडिया का साथ छोड़कर घर लौट गए हैं। दरअसल, लिवर कैंसर से जूझ रहे रिंकू के पिता खानचंद सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फिलहाल वे ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मीडिया सूत्र के अनुसार मुताबिक जब रिंकू को पिता के बारे में जानकारी मिली, उस वक्त वे चेन्नई में थे। बीसीसीआई के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की

है कि रिंकू प्रैक्टिस सेशन में भी शामिल नहीं हुए। परिवार में आई मेडिकल इमरजेंसी के कारण रिंकू का 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना भी मुश्किल लग रहा है।

पिता को फोर्थ स्टेज का लिवर कैंसर है- क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह को फोर्थ स्टेज का लिवर कैंसर है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद घरवालों ने उन्हें ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ओमेगा वन के यथार्थ अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल के मुताबिक- खानचंद सिंह को तत्काल इलाज की जरूरत थी। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी सेहत पर नजर रख रही है। पिता के हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर मिलते ही रिंकू सिंह मंगलवार सुबह 10 बजे अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने पिता के साथ कई घंटे बिताए, साथ ही डॉक्टरों से अपडेट भी लिया।

ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया

भारत और जिम्बाब्वे के बीच सुपर-8 का मुकाबला 26 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। रिंकू ने मंगलवार को ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, जबकि टीम के बाकी खिलाड़ी नेट्स पर मौजूद रहे। भारत के लिए यह मुकाबला अहम है, क्योंकि भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यह मैच बड़े अंतर से जीतना होगा।

वर्ल्ड कप के 5 मैच में 24 रन ही बना सके रिंकू- रिंकू सिंह भारतीय टीम में छठे या सातवें नंबर पर बैटिंग करते हैं। उन्हें टीम फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करती है।

ब्रूक शतक लगाने वाले पहले कप्तान

बाबर लोएस्ट स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज, इंग्लैंड लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल में

कोलंबो (एजेंसी)। इंग्लैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल में जगह बना ली। मंगलवार रात पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर टीम इस एडिशन के नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक बतौर कप्तान टी-20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। वहीं पाकिस्तान के बाबर आजम इस टूर्नामेंट में सबसे कम स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाजों में शामिल हो गए।

- **इंग्लैंड लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल में-** इंग्लैंड टी-20 वर्ल्ड कप में लगातार पांचवीं बार सेमीफाइनल में पहुंच गया है। टीम 2016 से 2026 तक लगातार पांच बार सेमीफाइनल में पहुंची है। इससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका चार-चार बार लगातार अंतिम चार में पहुंचे थे, लेकिन इंग्लैंड अब इस मामले में सबसे आगे निकल गया है।
- **बाबर आजम सबसे कम स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज-** टी-20 वर्ल्ड कप में जहां बल्लेबाजों से तेज रन बनाने की उम्मीद होती है, वहीं बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 111.5 रहा है, जो 500 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सबसे कम है। इस लिस्ट में हफीज, संगकारा और विलियमसन जैसे बड़े नाम भी हैं, लेकिन बाबर सबसे नीचे हैं।
- **शाहीन पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज-** शाहीन अफरीदी नई गेंद से टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित हुए हैं। उन्होंने पावरप्ले में 18 विकेट लेकर इस फेज में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया।
- **शाहीन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर-** पाकिस्तान के लिए टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अब शाहीन अफरीदी के नाम है। उन्होंने 102 मैचों में 135 विकेट लेकर हारिस रऊफ को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 133 विकेट हैं।

वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा

हैरी ब्रूक ने कप्तान रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 100 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। वह टी-20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बने। इससे पहले क्रिस गेल का 98 रन सर्वोच्च स्कोर था। ब्रूक टी-20 वर्ल्ड कप रन चेज में शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज भी बने।
ब्रूक दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज- हैरी ब्रूक ने 50 गेंदों में शतक लगाकर टी-20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा। वह सिर्फ क्रिस गेल (47 गेंद) से पीछे हैं। साथ ही ब्रूक इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बने। उनसे पहले जोस बटलर, डेविड मलान ऐसा कर चुके हैं।

अब पाकिस्तान का क्वालिफिकेशन दूसरों के भरोसे

इंग्लैंड टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। टीम ने मंगलवार को ग्रुप-2 में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया और नॉकआउट राउंड में एंट्री की। 2010 और 2022 की चैंपियन टीम ने लगातार पांचवें एडिशन के सेमीफाइनल में जगह बनाई।दूसरी ओर पाकिस्तान सुपर-8 स्टेज में एक भी मैच नहीं जीत सका। टीम को अब क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच जीतने के साथ न्यूजीलैंड के हारने की दुआ भी करनी होगी।

भारत को क्वालिफाई जीतना होगा दोनों मैच?

ग्रुप-1 पॉइंट्स टेबल में फिलहाल वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका 2-2 पॉइंट्स के साथ टॉप-2 पोजिशन पर हैं। भारत और जिम्बाब्वे आखिरी 2 पोजिशन पर हैं, दोनों का रन रेट माइनस में है।भारत को सीधे क्वालिफाई करने के लिए आखिरी दोनों मैच जीतने होंगे, साथ ही साउथ अफ्रीका के वेस्टइंडीज के खिलाफ जीतने की उम्मीद भी करनी होगी।भारत आखिरी दोनों मैच जीत गया और वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो 3 टीमों के 4-4 पॉइंट्स हो जाएंगे। ऐसे में क्वालिफाई करने के लिए भारत को अपना रन रेट बाकी टीमों से बेहतर रखना होगा।भारत अगर एक भी मैच हारा तो टीम नॉकआउट की रेस से बाहर हो जाएगी।

ग्रुप-1 में बाकी टीमों के क्या समीकरण हैं?- साउथ अफ्रीका अब वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। टीम एक भी मुकाबला हारी तो उन्हें अपना रन रेट बेहतर रखना होगा। दोनों मैच हारने पर टीम बाहर हो जाएगी। वेस्टइंडीज को क्वालिफाई करने के लिए साउथ अफ्रीका और भारत के खिलाफ आखिरी दोनों मैच जीतने होंगे। टीम एक भी मुकाबला हारी तो उन्हें अपना रन रेट बेहतर रखना होगा। दोनों मैच हारने पर टीम बाहर हो जाएगी।जिम्बाब्वे एक मैच हार चुकी है। टीम को क्वालिफाई करने के लिए भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दोनों मैच जीतने ही होंगे। एक भी मैच हारने पर टीम बाहर हो जाएगी।

इंग्लैंड नॉकआउट में पहुंचा, पाकिस्तान की उम्मीदें कम

ग्रुप-2 में 4 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी मैच जीतकर टीम अपने ग्रुप में नंबर-1 पर फिनिश कर सकती है। अगर श्रीलंका से न्यूजीलैंड जीता तो श्रीलंका बाहर हो जाएगी, फिर टीम पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मैच जीतकर भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी।

16 साल पहले आज ही सचिन ने लगाया था दोहरा-शतक

उनके बाद 4 भारतीयों ने डबल सेंचुरी लगाई, रोहित के नाम सबसे बड़ा स्कोर

नईदिल्ली (एजेंसी)। 16 साल पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इतिहास रचा था। 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सचिन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। इस ऐतिहासिक पारी में सचिन ने 147 गेंदों का सामना करते हुए 25 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 200 रन बनाए। यह वनडे इतिहास का पहला ही दोहरा शतक था।

सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ा था- वनडे क्रिकेट में सचिन से पहले 2 बैटर्स 194 तक पहुंचे थे। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सईद अनवर ने 1997 में भारत के खिलाफ चेन्नई में ही 194 रन बनाए थे। 2009 में फिर जिम्बाब्वे के चार्ल्स कॉवेंट्री ने बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 194 रन की पारी खेली थी।

- **सचिन ने 5 बार 150+ का स्कोर बनाया-** सचिन ने वनडे इंटरनेशनल में 5 बार 150 या उससे ज्यादा के स्कोर बनाए। डबल सेंचुरी के अलावा सचिन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 186, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 175, न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 163 और नामीबिया के खिलाफ 152 रन बनाए हैं।

स्टीव बकनर ने माना- तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू देना गलती थी

अंपायर स्टीव बकनर ने सचिन तेंदुलकर को गाबा टेस्ट में आउट होने पर माना है कि उनसे गलती हो गई थी। वेस्टइंडीज के पूर्व अंपायर ने मैच के 22 साल बाद कहा कि आज भी लोग उनसे इसके बारे में सवाल करते हैं।दरअसल, 2003-04 में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर स्टीव बकनर ने सचिन तेंदुलकर को एलबीडब्ल्यू आउट दिया था। यह मैच ड्रॉ हो गया था। 4 मैचों की सीरीज भी 1-1 से बराबरी पर रही थी।

3 रन पर आउट हुए थे तेंदुलकर- पहले टेस्ट में सचिन तेंदुलकर 3 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी की गेंद को उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी। जोरदार अपील के बाद स्टीव बकनर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। बाद में टीवी रीप्ले में स्पष्ट हुआ कि गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी।

शिखर धवन केस में बड़ा फैसला

पूर्व पत्नी को 5.7 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश

दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला

नईदिल्ली (एजेंसी)। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन की पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। धवन ने यह पैसा आयशा को तलाक के बाद सेटलमेंट के रूप में दिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट का मानना है कि धवन की ओर से प्रॉपर्टी सेटलमेंट के रूप में दी गई यह रकम भारतीय कानून के हिसाब से सही नहीं है। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट का फैसला भारत पर लागू नहीं होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा है कि आयशा ऑस्ट्रेलिया की अदालत के फैसले के तहत शिखर धवन से 16.9 करोड़ रुपए की डिमांड नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, भारतीय फैमिली लॉ एक्ट 1975 के तहत प्रॉपर्टी सेटलमेंट का नियम भारतीय मैट्रिमोनियल लॉ और हिंदू मैरेज एक्ट 1955 के साथ ही मेल खाता है। लिहाजा आयशा ने प्रॉपर्टी सेटलमेंट नियम के तहत जो 5.7 करोड़ की रकम ली है, उसे शिखर धवन को लौटाना होगा।

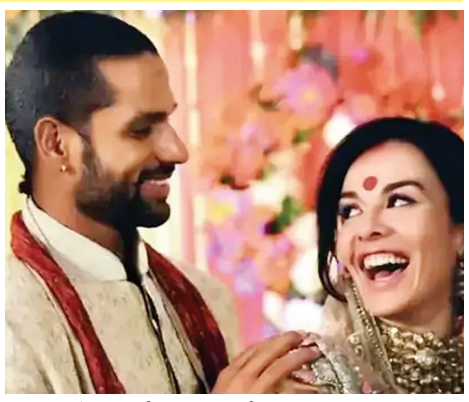

ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत 60 प्रतिशत हिस्सेदारी का आदेश- ऑस्ट्रेलिया के कानून के तहत पति की सभी प्रॉपर्टी को मेराइटल पूल में माना जाता है। इसी कानून के तहत ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन की भारत और विदेश में स्थित सभी संपत्तियों में से 60 फीसदी हिस्सा उनकी पत्नी आयशा को देने का आदेश दिया था। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन के लिए 1975 एक्ट की धारा 79 का इस्तेमाल किया था और उन्हें प्रॉपर्टी बेचकर 8.12 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर देने का आदेश दिया था।

दिल्ली कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई आदेश पर सवाल उठाए- दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आयशा कोर्ट में पेश भी नहीं हुई हैं और ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने धवन के खिलाफ एकतरफा फैसला सुनाया था। ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने कहा था कि धवन ऑस्ट्रेलिया में मौजूद अपनी सभी संपत्तियों को बेचकर सारा पैसा पत्नी आयशा को दें। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने यह भी पाया कि धवन को जबरिया 82 हजार डॉलर का भुगतान करना पड़ा था। कोर्ट ने फैसले में आयशा को प्रॉपर्टी बेचकर मिली 5.70 करोड़ की रकम धवन को लौटाने का भी आदेश दिया है।

क्या कहता है भारतीय कानून- भारत में मैरिज एक्ट के तहत प्रॉपर्टी सेटलमेंट का कोई एक समान और स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन अलग-अलग धर्मों के हिसाब से इसे लागू किया जाता है। हिंदू मैरेज एक्ट के तहत धारा 27 में तलाक के समय पति-पत्नी के संयुक्त मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाता है। इस कानून में स्त्रीधन का प्रावधान है, जो पत्नी को मिले गिफ्ट, ज्वैलरी, फर्नीचर आदि के रूप में होता है और तलाक के समय यह संपत्ति सिर्फ पत्नी को दी जाती है। कानून की धारा 25 के तहत तलाक की स्थिति में पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होता है।

2023 में हुआ था तलाक

धवन और उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी का अक्टूबर 2023 में आधिकारिक तौर पर तलाक हुआ था। दोनों की शादी 2011 में हुई थी और यह रिश्ता करीब 11 साल चला। आयशा की पहले की शादी से दो बेटियां हैं। धवन के साथ उनका बेटा जोरावर है।

2024 में लिया था संन्यास

धवन ने 2010 में टी-20 और 2011 में भारत के लिए वनडे डेब्यू किया। हालांकि, टीम में जगह बनाने में उन्हें 3 साल लग गए। 2013 में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया, यहीं से वे तीनों फॉर्मेट में फिक्स हो गए। उन्होंने 10 दिसंबर 2022 तक भारत के लिए 167 वनडे, 68 टी-20 और 34 टेस्ट खेले।

रणजी ट्रॉफी फाइनल- पहले दिन जम्मू-कश्मीर का स्कोर 284/2

पुंदीर ने शतक लगाया, समद और यावर की फिफ्टी, प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट

जम्मू (एजेंसी)। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बीच हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। जम्मू-कश्मीर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। पहले दिन जम्मू-कश्मीर ने मजबूत शुरुआत करते हुए 2 विकेट खोकर 284 रन बना लिए। शुभम पुंदीर 117 और अब्दुल समद 52 रन नॉटआउट लौटे। कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों विकेट लिए।

- **शुभम शतक बनाकर नाबाद-** शुभम पुंदीर ने पहले दिन नाबाद शतक लगाया। उन्होंने 221 गेंद पर 12 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 117 रन बनाए। शुभम ने यावर हसन के साथ दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। कप्तान पारस डोगरा 9 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए।
- **शुभम और अब्दुल ने नाबाद 105 रन जोड़े-** दिन का आखिरी सेशन पूरी तरह जम्मू-कश्मीर के नाम रहा। शुभम और अब्दुल समद ने तीसरे विकेट के लिए नाबाद 105 रन जोड़े। अब्दुल समद ने दिन का खेल खत्म होने से पहले अपना अर्धशतक किया। वह 52* रन बनाकर नॉटआउट लौटे।
- **जम्मू-कश्मीर ने 18 रन पर गंवाया पहला विकेट-** टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी जम्मू-कश्मीर की शुरुआत खराब रही।
टीम ने 18 रन के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया। यहां करीम इकबाल 6 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराया।
- **शुभम और यावर के बीच शतकीय साझेदारी-** पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद शुभम पुंदीर बल्लेबाजी के लिए उतरे। शुभम और यावर हसन ने दूसरे विकेट के लिए 139 रनों की साझेदारी की। दोनों ने करीब 40 ओवर तक बैटिंग की। इस बीच यावर और शुभम ने अपने अर्धशतक भी पूरे किए।
- **प्रसिद्ध ने तोड़ी शतकीय साझेदारी-** शुभम पुंदीर और यावर हसन की शतकीय साझेदारी को प्रसिद्ध कृष्णा ने ब्रेक किया। उन्होंने 51वें ओवर की छठी बॉल पर यावर हसन को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराया। यावर ने 150 बॉल पर 88 रन बनाए।
- **जम्मू-कश्मीर ने दो बदलाव किए-** फाइनल में जम्मू-कश्मीर ने दो बदलाव किए।

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक अन्नपूर्णा गुप्ता द्वारा भास्कर प्रिंटिंग प्रेस प्लांट नं. 535 एवं 1272, लालगुटवा रातू पुलिस स्टेशन रांची में मुद्रित तथा विजय जनरल स्टोर, हिनू चौक रांची-834002 से प्रकाशित समस्त दिवानी विवाद न्यायोचित एवं दंडित परिवादों के लिए क्षेत्राधिकारी रांची न्यायालय में रहेगा। पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के जिम्मेदार। **प्रधान संपादक**-अन्नपूर्णा गुप्ता, कार्यायल नं.0651-2253830,मो.9471717919, 7895244551 ईमेलः alagpahchan@gmail.com, www.alagpahchan.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन 2013 JHAHINO0575 RNI No.JHAHIN(2013) 66670